

संक्षिप्त समाचार

आयुष्मान कार्ड शिविर शुरू, पांच दिसंबर तक फ्री में बनवाए आयुष्मान कार्ड

रायपुर। रायपुर जिला प्रशासन की ओर से 3, 4 और 5 दिसंबर को आयुष्मान कार्ड महाअभियान का आयोजन किया गया है। समय-सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक बनेगा। इस सुविधा का लाभ उठाकर लोग अपना और अपने परिवार के सदस्यों का आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। साथ ही 70 एवं 70 वर्ष से अधिक वरिष्ठ नागरिकों का आयुष्मान वय वंदना कार्ड निःशुल्क बनाये जाएंगे। नागरिकों को इस सुविधा का लाभ लेने के लिये अपना जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे- राशनकार्ड, आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो लेकर अपने नजदीकी च्याइस सेंटर, समस्त शासकिय स्वास्थ्य संस्थानों और चिह्नित शिविर स्थल (समस्त वार्ड) में जाकर अपना और अपने परिवार के सदस्यों का फ्री में आयुष्मान कार्ड पंजीयन करा सकते हैं। आयुष्मान कार्ड महाअभियान में शिविर स्थल के संबंध में अधिक जानकारी के लिए अपने वार्ड पार्षद, मितानिन, जोन कार्यालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय या टोल फ्री नंबर 104 पर संपर्क कर सकते हैं।

गार्डन में धादर चक्र लोकर खड़ा था बदमाश, पुलिस ने मौके पर दबोवा

रायपुर। रायपुर एसएसपी डॉ. संतोष सिंह के निर्देशानुसार अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने और चक्रबजों के ऊपर कार्रवाई के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना पुरानी बस्ती पुलिस ने अवैध रूप से चक्र रखे चक्रबाज को गिरफ्तार किया है। पुलिस को मुखबिर् से सूचना मिली कि बूढ़ा तालाब गार्डन के पास में एक व्यक्ति खड़ा है। वह अपने पास अवैध रूप से चक्र रखा है। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर खाना होकर मुखबिर् के बताए अनुसार जगह पर पहुंची। इस दौरान अपराधी पुलिस को देख भागने की कोशिश की, लेकिन भागने में असफल रहा। आरोपी का तलाशी लेने पर आरोपी के कब्जे से अवैध रूप से एक नग लोहे की धादर चक्र मिला। इस पर आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज किया गया।

अब तक 20.54 लाख मीट्रिक टन धान की हुई खरीदी

रायपुर। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी जारी रही है। 14 नवंबर से शुरू हुए धान खरीदी का सिलसिला अनवरत रूप से जारी है। राज्य में 14 नवंबर से अब तक 20.54 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। राज्य में अब तक 4.36 लाख किसानों ने अपना धान बेचा है। धान खरीदी के एवज में इन किसानों को बैंक लिफिंग व्यवस्था के तहत 4285 करोड़ 74 लाख रुपये का भुगतान किया गया है। धान खरीदी का यह अभियान 31 जनवरी 2025 तक चलेगी। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस खरीद वर्ष के लिए 27.68 लाख किसानों की ओर से पंजीयन कराया गया है। इसमें 1.45 लाख नए किसान शामिल हैं। इस वर्ष 2739 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी अनुमानित है। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि एक दिसंबर को 45455 किसानों से 2.08 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की गई है। इसके लिए 62966 टोकन जारी किए गए थे। आगामी दिसंबर के लिए 38508 टोकन जारी किए गए हैं।

टाटानगर-बिलासपुर-टाटानगर एक्सप्रेस कल से चलेगी अपने निर्धारित समय पर

रायपुर। दक्षिण पूर्व रेलवे के कोटशिला स्टेशन में याद रिमोंडलिंग एवं अन्य संरक्षा संबंधित कार्य हेतु पावर ब्लॉक के फलस्वरूप 1से4 दिसम्बर तक गाड़ी संख्या 18113/18114 टाटानगर-बिलासपुर-टाटानगर एक्सप्रेस को रद्द किया गया था जिसे यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुये 4 दिसंबर को रिस्टोर कर दिया गया है। गाड़ी संख्या 18113/18114 टाटानगर-बिलासपुर-टाटानगर एक्सप्रेस 4 दिसंबर को अपने निर्धारित समयानुसार चलेगी।

यूपी का मोबाइल चोर भिंडी गिरफ्तार

रायपुर। उत्तरप्रदेश के मौदहा में रहने वाले



शहजादा अली उर्फ भिण्डी को खम्हारडीह पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भिण्डी ने बाइक में घूम-घूम कर दर्जन भर मोबाइल फोन को चोरी कर बेचा करता है। अलग अलग थानों से चोरी के कई प्रकरणों में भिण्डी जेल जा चुका था। अपराध प्रवीण ने सोमवार शाम थाना खम्हारडीह में रिपोर्ट दर्ज कराई थी शंकर नगर स्थित क्रिस्टल अकाउंट पास मोटर सायकल सवार एक अज्ञात युवक आकर के हाथ से उसके आई फोन मोबाइल को झपटा मारकर छीनकर ले गया। उसकी कीमत 65 हजार से अधिक है। इस रिपोर्ट पर पुलिस ने धारा 304 (2) बी.एन.एस. का अपराध दर्ज कर तलाश शुरू की। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने पर टीम को शातिर चोर शहजादा अली उर्फ भिण्डी के संबंध में जानकारी मिली। उसे पकड़कर पृच्छाछ में उसने कल की घटना स्वीकार करते हुए बाइक में घूम-घूम कर रायपुर के अलग-अलग स्थानों से राहगीरों के हाथों से अन्य 10 मोबाइल फोन झपटा मार छीनना बताया गया और उससे 11 मोबाइल फोन, मोटर सायकल बरामद किया गया।

भाजपा मना रही है जनादेश दिवस, जनता के फैसले का जताया आभार

रायपुर। छत्तीसगढ़ में 3 दिसंबर 2023 को आए नतीजों में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंका था। इन नतीजों ने हर किसी को चौंका दिया था। क्योंकि 15 साल तक सत्ता में रहने वाली बीजेपी को साल 2018 में कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत के साथ हराया था। ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस वापसी करेगी। लेकिन ऐसा हो ना सका जब नतीजे आए तो बीजेपी ने 54 सीटों के साथ अप्रत्याशित जीत दर्ज की। जिसकी पार्टी को भी उम्मीद ना थी। ऐसे में 3 दिसंबर के दिन को बीजेपी जनादेश दिवस के तौर पर मना रही है।



सीएम विष्णुदेव साय और प्रदेशाध्यक्ष किरण देव सिंह ने जनादेश दिवस पर जनता को धन्यवाद ज्ञापित किया है। इस दिन विगत एक वर्ष में हमारी सरकार ने आपके विश्वास पर खरा उतरते हुए प्रदेश में प्रगति के अनेक नए आयाम स्थापित किए हैं। हमने 'मोदी की गारंटी' के सभी प्रमुख वादे प्राथमिकता से पूरे किए हैं। हमारी सरकार इसी निरंतरता को बनाए रखते हुए प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए तत्पर है।

इस अवसर पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष किरण देव सिंह ने जनता का आभार व्यक्त किया। किरण देव सिंह ने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि देवतुल्य जनता का आभार भाजपा के प्रति विश्वास और आशीर्वाद के लिए आभार। हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं को हार्दिक शुभकामनाएं। भाजपा ने आज ही के दिन विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक विजय प्राप्त की थी। भाजपा की सुशासन सरकार छत्तीसगढ़ में विकास की नई गाथा लिख रही है।

सैनिकों के कल्याण के लिए मानवीय संवेदना से कार्य करें: डेका

सैनिक कल्याण बोर्ड छत्तीसगढ़ के राज्य प्रबंधन समिति की बैठक सम्पन्न

रायपुर। राज्यपाल श्री रमेन डेका की अध्यक्षता में आज राजभवन में सैनिक कल्याण बोर्ड छत्तीसगढ़ के राज्य प्रबंधन समिति की 16वीं बैठक सम्पन्न हुई। इस बैठक में भूतपूर्व सैनिकों, विधवाओं, व उनके आश्रितों के लिए सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा की गई एवं भूतपूर्व सैनिकों के हितों में महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये। राज्यपाल ने कहा कि भारत माता की सेवा में अपना जीवन गुजराने वाले वीर सपूतों का कल्याण करना सबका दायित्व और कर्तव्य है। इसमें मानवीय संवेदना के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। इस दिशा में हम सभी को विशेष ध्यान देना चाहिए।



सहायता पर ही निर्भर ना रहते हुए समुदाय को भी इसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों के कल्याण के लिए और अधिक योजनाएं शुरू की जा सकें। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आज की बैठक में लिये गये सभी निर्णयों से छत्तीसगढ़ में भूतपूर्व सैनिक उनके लाभान्वित होंगे। डेका ने राज्य के दूरदराज के इलाकों में कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ की सैनिक कल्याण टीम द्वारा किए गए प्रयासों की सरहना की और कहा कि समर्पण के साथ देश की सेवा करने वाले हमारे बहादुर पूर्व सैनिकों की अच्छी तरह से देखभाल की जाए।

बैठक के दौरान भूतपूर्व सैनिकों, विधवाओं एवं उनके आश्रितों के हित में कई बिन्दुओं पर निर्णय लिये गये। जिसमें जवानों की भांति जूनियर कमिश्नड ऑफिसर (जे.सी.ओ.) के लिये भी पुत्री विवाह हेतु 50 हजार रूपए का आर्थिक अनुदान तथा चार्टर्ड एकाउटेन्ट, कंपनी सेक्टरी के व्यवसायिक पाठयक्रम का अध्ययन करने वाले बच्चों को 20 हजार रूपए एकमुश्रत प्रतिवर्ष का आर्थिक अनुदान प्रदान किया जायेगा। समिति ने जिला सैनिक कल्याण कार्यालय जगदलपुर के द्वितीय तल पर सभागार का निर्माण एवं भूतल पर दिव्यांग भूतपूर्व सैनिकों के लिए कमरा निर्माण के प्रस्ताव को अनुमोदित किया। सैनिक कल्याण बोर्ड के संचालक श्री विवेक शर्मा ने बोर्ड की अग्त बैठक की गतिविधियों एवं वज्र के संबंध में प्रस्तुतिकरण दिया।

नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने राज्यपाल को लिखा पत्र

कहा- आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों से अपात्र लोगों को हटाया जाए

रायपुर। विधानसभा नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को पत्र लिखकर अनुसूचित क्षेत्र की आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों से विधि विरुद्ध अपात्र व्यक्तियों को तत्काल हटाने की मांग की है। पत्र में कहा गया है कि नवंबर 2024 में अनुसूचित क्षेत्र में संचालित राज्य के अनेक आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों में प्राधिकृत अधिकारी बतौर ऐसे अशासकीय व्यक्तियों को बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करने प्राधिकृत किया गया है, जो अनुसूचित जनजाति वर्ग के नहीं हैं। यह कृत्य छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के विरुद्ध है।



नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने अपने पत्र में लिखा है कि छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 48 की उपधारा (5) के खंड (दो) के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र में संचालित संसाधन सोसायटी में अध्यक्ष या सभापति का निर्वाचन केवल अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों में से किया जाएगा। अनुसूचित क्षेत्र जिला कोरिया की आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों-धौराटिकरा के लिए जारी किए गए हैं। इसी

प्रकार के अन्य अनेक आदेश और भी है, जिनमें अन्य वर्ग के व्यक्तियों को प्राधिकृत किया गया है। विधिक प्रावधानों की मंशा के विरुद्ध इस तरह अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित स्थानों पर उनके वैधानिक अधिकारों की घोर उपेक्षा करके अन्य वर्ग के व्यक्तियों को नियुक्त किया जाना उचित नहीं है। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने राज्यपाल से आग्रह किया है कि राज्य सरकार को निर्देशित करने का कष्ट करें कि अनुसूचित क्षेत्र में आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के अशासकीय व्यक्तियों को ही बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाए। जहां भी विधि विरुद्ध अपात्र व्यक्तियों को प्राधिकृत किया गया है वहां उनको तत्काल हटाते हुए पात्र व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जाए।

भाजपा सरकार अपने वादों पर खरी नहीं उतरी, किसानों के साथ जबरदस्त धोखाधड़ी: ताम्रध्वज साहू

दुर्गा। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर अनियमितता का आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सरकार किसानों के साथ किए गए वादों में निभा रही है। किसानों के साथ सरकार छल कर रही है। इसी कड़ी में प्रदेश के पूर्व गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू मंगलवार को ग्राम कोलियापुरी के धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान पूर्व गृहमंत्री ने किसानों के साथ बातचीत की।



छत्तीसगढ़ के पूर्व गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू और दुर्गा शहर के पूर्व विधायक अरुण चोरा आज कोलियापुरी के धान खरीदी केंद्र निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने धान खरीदी को लेकर भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस का कहना है कि किसानों को जबरदस्त नुकसान हो रहा है। वर्तमान भाजपा की सरकार कांग्रेस ने जो किया, उसके ठीक विपरीत आचरण कर रही है। ताम्रध्वज साहू ने कहा 3100 रूपए में धान खरीदने की बात कही गई थी, हम लोगों ने जानकारी लिया तो बताया गया कि अभी मात्र 2300 रूपए का भुगतान किया जा रहा है। जो एमएसपी रेट बढ़ा है उसका और बोनस का किसी भी तरह का भुगतान नहीं

किया गया है। 800 क्विंटल धान खरीदी करना एक दिन में करना है, तो केवल 600 से 700 क्विंटल ही खरीद रहे हैं। बाकी 100 से 200 क्विंटल को कब खरीदेंगे, इसकी भी जानकारी नहीं दे रहे हैं। यह पूर्णतः किसानों के साथ धोखा है। पूर्व गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने आरोप लगाया कि जो बारदाना दिया गया है, उसको काटा तौल कर देखा गया तो 40 किलो धान लेना है, लेकिन 41 साढ़े 41 किलो धान काटे में दिखाई दिया। अनावली गिरदावली के जरिए उनका रिपोर्ट कम करा दिए हैं। कहीं 17 क्विंटल तो कहीं 16 क्विंटल, उस हिस्साब से धान खरीदने की बात कर रहे हैं। प्रति एकड़ 21 क्विंटल की बात नहीं कर रहे हैं। ताम्रध्वज साहू ने कहा कांग्रेस सरकार में जो खुशहाली किसानों के चेहरे पर थी, वो

बीजेपी के शासन काल में खत्म हो गई है। भाजपा की सरकार अपने वादों पर खरी नहीं उतर रही है। किसानों के साथ जबरदस्त धोखाधड़ी की जा रही है। किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ताम्रध्वज साहू ने आगे कहा कि धान खरीदी केंद्र में कई प्रकार की कठिनाइयां हैं। टोकन ऑनलाइन कर दिए गए, उसमें भी 1 माह बाद की डेट मिल रही है। ऑनलाइन टोकन में भी समस्या हो रही है। सूखत काटने का नहीं है, लेकिन किसानों से सुखत लिया जा रहा है। इनके इलेक्ट्रॉनिक कांटा में भी किसानों को संदेह है। ये कांटा सही नहीं है। धान मिसाई, लुआई किसान 15 से 20 दिन पहले कर चुका है। धान लाने की रखने की समस्या है। इस तरह बहुत सारी तकलीफों का सामना किसानों को करना पड़ रहा है।

भाजपा की सरकार अपने वादों पर खरी नहीं उतर रही है। किसानों के साथ जबरदस्त धोखाधड़ी की जा रही है। किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ताम्रध्वज साहू ने आगे कहा कि धान खरीदी केंद्र में कई प्रकार की कठिनाइयां हैं। टोकन ऑनलाइन कर दिए गए, उसमें भी 1 माह बाद की डेट मिल रही है। ऑनलाइन टोकन में भी समस्या हो रही है। सूखत काटने का नहीं है, लेकिन किसानों से सुखत लिया जा रहा है। इनके इलेक्ट्रॉनिक कांटा में भी किसानों को संदेह है। ये कांटा सही नहीं है। धान मिसाई, लुआई किसान 15 से 20 दिन पहले कर चुका है। धान लाने की रखने की समस्या है। इस तरह बहुत सारी तकलीफों का सामना किसानों को करना पड़ रहा है।

सोसायटी तक पहुंच रहे हैं कांग्रेसी और किसानों से पूछकर यह जान रहे हैं धान विक्री का हाल। धरसीवा, सांकरा ब्लॉक में पूर्व विधायक सत्यनारायण शर्मा,धनेन्द्र साहू, विकास उपाध्याय के साथ पूर्व राज्यसभा सदस्य छाया वर्मा,अनिता शर्मा,पंकज शर्मा,उद्धव राम वर्मा,शैलेश नीतिन द्विवेदी,पप्पू बंजारे विभिन्न धान खरीदी केंद्रों में जाकर किसानों से मिले। धान खरीदी केंद्रों के निरीक्षण के बाद बोले कांग्रेस नेताओं ने बताया कि धान खरीदी केंद्रों में टोकन नहीं कट रहा है,किसानों से सूखत के नाम पर अधिक धान लिया जा रहा है,धान खरीदी केंद्रों से एक बार भी उठाव नहीं किया गया है,धान बेचने के लिए किसानों को काफी परेशानी हो रही है,खरीदी केंद्र में दिया गया आंकड़ा पूरा नहीं हो पा रहा है।

ताम्रध्वज साहू ने आगे कहा कि धान खरीदी केंद्र में कई प्रकार की कठिनाइयां हैं। टोकन ऑनलाइन कर दिए गए, उसमें भी 1 माह बाद की डेट मिल रही है। ऑनलाइन टोकन में भी समस्या हो रही है। सूखत काटने का नहीं है, लेकिन किसानों से सुखत लिया जा रहा है। इनके इलेक्ट्रॉनिक कांटा में भी किसानों को संदेह है। ये कांटा सही नहीं है। धान मिसाई, लुआई किसान 15 से 20 दिन पहले कर चुका है। धान लाने की रखने की समस्या है। इस तरह बहुत सारी तकलीफों का सामना किसानों को करना पड़ रहा है।

कांग्रेस के 'धान खरीदी केंद्र चलो' अभियान पर सीएम साय का तंज

रायपुर। कांग्रेस का धान खरीदी केंद्र चलो अभियान मंगलवार से शुरू हुआ। इस पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने तंज कसते हुए कहा कि अच्छा है जाएं। दूर से बैठकर ब्लेम करने की बजाए खरीदी केंद्र में जाएं। उनको वास्तविकता का पता चलेगा। रायगढ़ में मंगलवार को होने वाले विभिन्न कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मीडिया से चर्चा में मंगलवार को जारी होने वाली महतारी वंदन योजना की 10वीं किश्त को लेकर कहा कि मोदी की गारंटी में एक बड़ा वादा ये भी था कि महतारी वंदन योजना के तहत एक हजार रूपए देंगे। लगातार ये काम कर रहे हैं। हर महीने के पहले हफ्ते में ही एक हजार देने का काम कर रहे हैं। मंगलवार को दिसंबर माह की किश्त भी रायगढ़ से हितग्राहियों के खाते में अंतरित करेंगे।

30 मेडिकल स्टोर्स पर खाद्य एवं औषधि विभाग ने मारा छापा

रायपुर। औषधि विभाग एवं रायपुर पुलिस विभाग के लगभग 50 अधिकारियों के कुल 11 संयुक्त टीमों के द्वारा रायपुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों माना, खरोख, बिरगांव, हीरापुर, संतोषी नगर, रायपुर, कबीरनगर, टिकरपारा, अवंतिविहार, लाभांडी, शंकरनगर, गुडियारी, चंगोराभाटा आदि में संचालित कुल 30 मेडिकल स्टोर्स में नशीली दवाओं के अवैध व्यापार पर नियंत्रण हेतु छाापामार कार्यवाही की गई। छाापामार कार्यवाही में टेस्ट परचेस किया गया। रायपुरा स्थित जय दुर्गा मेडिकल स्टोर्स में बिना



प्रिस्क्रीपसन के नारकोटिक्स दवाओं का विक्रय पाया गया जिसमें विभाग द्वारा कानूनी कार्यवाही की जा रही है तथा 04 दुकानों 1. दिनेश मेडिकल स्टोर्स, चंगोराभाटा 2. श्री मेडिकल

स्टोर्स, खरोरा 3. गुजरात मेडिकल स्टोर्स, खरोरा एवं 4. जय दुर्गा मेडिकल स्टोर्स, रायपुरा में नारकोटिक्स दवाएं बरामद किया गया है जिनका कय विक्रय अभिलेख फर्म द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सका एवं इन मेडिकल स्टोर्स के विरूद्ध औषधि से संबंधित प्रचलित कानूनों के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है। अन्य दुकानों में औषधि नियमावली को अनियमितता पाई गई जिन्हे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु नोटिस दिया जायेगा। संतोषप्रद जबाब नहीं पाये जाने पर विभाग द्वारा औषधि नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। औषधि विभाग

द्वारा नशीली दवाओं के विक्रय के संबंध में विगत 6 माह में रायपुर जिला के विभिन्न 52 औषधि प्रतिष्ठानों को स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया गया जिसमें से 33 मेडिकल दुकानों की अनुज्ञासिओं को निलंबित तथा 05 मेडिकल दुकानों के अनुज्ञासिओं को निरस्त किया गया है। राज्य के समस्त जिलों के मेडिकल स्टोर्स में नशीली दवाओं के अवैध विक्रय में नियंत्रण हेतु आगामी समय में इसी प्रकार औषधि विभाग एवं रायपुर पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से चरणबद्ध तरीकों से कार्यवाही की जावेगी।

कार्यालय कार्यपालन अभियंता लोक स्वा. यां. परियोजना खंड, रायपुर

निविदा क्रमांक 03/बलेवलि/ रायपुर दिनांक 26.11.2024	
निविदा आमंत्रण सूचना	
मुहरबंद निविदायें नीचे उल्लेखित कार्य हेतु प्रपत्र 'अ' प्रतिशत दर में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की ओर से अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में ई-पंजीयन प्रणाली की 'डी' एवं उच्च श्रेणी में पंजीबद्ध ठेकेदारों से स्प्रीड पोस्ट द्वारा आमंत्रित की जाती है।	
1. निविदा प्रपत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत - 11.12.2024 सार्वा 5.30 बजे तक करने की अंतिम तिथि	
स. क्र.	कार्य का नाम
1.	रायपुर जिले में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी परियोजना उपखण्ड क्रमांक 02 रायपुर का मरम्मत एवं रंग रंगाना का कार्य।
	ठेके की अनुमानित लागत
	2.08 लाख
निविदा की अन्य शर्तें तथा कार्य की विस्तृत जानकारी अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखी जा सकती है।	
कार्यालय अभियंता लोक स्वा. यां. परियोजना खंड रायपुर (छ.ग.)	
जी-242504253/3	

हर चुनाव नेताओं की नाकामियों और कामयाबियों को दर्शाता है

कल्याणी शंकर

हर राजनीतिक दल गलतियाँ करता है, लेकिन समझदार दल उनसे सीखकर आगे बढ़ता है। किसी भी पार्टी की वृद्धि और सफलता के लिए पिछली गलतियों को ध्यान में रखना चाहिए और उन्हें भविष्य की प्रगति के लिए कदम के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। कांग्रेस 6 महीने पहले 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद अपनी सीटों को दोगुना करने के बाद गति बनाए नहीं रख सकी। इसके प्रदर्शन में गिरावट का कारण क्या था? क्या भारत की सबसे पुरानी कांग्रेस पार्टी सीखने और अनुकूलन के अवसरों को धुनाने में विफल रही? क्या एन.सी.पी. और शिवसेना के उड़द गट्टे ने संकेतों की गलत व्याख्या की? क्या झारखंड में भाजपा ने गलतियाँ कीं? महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों के हालिया नतीजों से विकास के अवसरों के चुकने का पता चलता है। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों में 2 बरतें सामने आई हैं। पहली बात यह है कि महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाली एन.डी.ए. की जीत का आकार, जिसने एन.सी.पी. और उड़द शिवसेना को हराया, जो पहले महाराष्ट्र में शासन कर चुकी थीं, और दूसरी बात यह कि हेमंत सोरेन ने झारखंड को कितनी आसानी से बर्करार रखा। दोनों अपने-अपने राज्यों में शासन कर रहे थे। अगर कांग्रेस ने पिछले अनुभवों से सीखा होता और आवश्यक समायोजन किए होते तो यह बेहतर प्रदर्शन कर सकती थी। पंचमढ़ी या शिमला सम्मेलनों के विपरीत, यहां चुनाव-पश्चात विश्लेषण का अभाव रहा है। कांग्रेस को आत्मनिरीक्षण की इस कमी को दूर करना चाहिए। यह पीढ़ीगत बदलाव के कारण नहीं हो सकता, क्योंकि बदलाव निरंतर होता है। आने वाली पीढ़ियों को पार्टी को आगे ले जाने के लिए काम करना चाहिए। बड़ी पुरानी पार्टी पूरी तरह से विपक्ष के नेता राहुल गांधी और उनके चुने हुए सहयोगियों के नियंत्रण में है। राहुल ने कड़ी मेहनत की और प्रचार किया, लेकिन पार्टी को अभी भी मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक लाना होगा। नतीजों से पता चलता है कि उन्होंने हाल ही में हरियाणा विधानसभा चुनावों से कुछ नहीं सीखा है, जैसे कि एक नेता पर बहुत अधिक निर्भर रहना, दूसरों की अनदेखी करना और जीतने की स्थिति में होने के बावजूद टिकटों का गलत वितरण। कांग्रेस पार्टी, एन.सी.पी. और शिवसेना के उड़द खेमे को जिस सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान देना चाहिए, वह है कथानक। कांग्रेस के लिए, जाति के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना, संविधान की रक्षा करना और प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत हमले करना मतदाताओं को पसंद नहीं आया है। यह अलगाव एक स्पष्ट संकेत है कि पार्टी को अपनी रणनीति का पुनर्मूल्यांकन करने और उन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है जो वास्तव में मतदाताओं को आकर्षित करते हैं, जैसे कि रोजी और मकखन के मुद्दे। यह एक गंभीर चिंता का विषय है, जिस पर एकमत होने की आवश्यकता है। 'इंडिया' गठबंधन के भीतर भी अब मतभेद हैं। हाल के परिणामों के बाद, 'इंडिया' ब्लॉक में भागीदार, जैसे कि 'आप' और तृणमूल कांग्रेस, अपने स्वयं के एजेंडे पर काम कर रहे हैं और संसद के वर्तमान शांतिपूर्ण सत्र के लिए संयुक्त कार्रवाई में बहुत कम रुचि दिखा रहे हैं। इससे पहले भी, राहुल गांधी के सावरकर पर हमले ने कांग्रेस को कोई समर्थन नहीं दिलाया था; इसके बजाय, इसने शिवसेना, जो सावरकर को आदर्श मानती थी और कांग्रेस के बीच मतभेद पैदा कर दिया था। इन दलों को भाजपा के मूल संगठन, आर.एस.एस. के राजनीतिक प्रभाव को एहसास नहीं था, जिसने पार्टी की सफलता के लिए काम किया। 'इंडिया' ब्लॉक ने लोकसभा चुनावों के दौरान मुद्दों को स्पष्ट नहीं किया, केवल भाजपा और उसके सहयोगियों को हराने पर ध्यान केंद्रित किया। इस रणनीति ने लोकसभा परिणामों को प्रभावित किया, जिससे भाजपा को 2 क्षेत्रीय दलों, जद (यू) और तेलुगु देशम पार्टी के समर्थन से सरकार बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। मराठा दिग्गज शरद पवार अपनी पार्टी और चुनाव अपने भतीजे, अजित पवार से हारने के बाद निराशा महसूस कर रहे होंगे, जिन्हें उन्होंने तैयार किया था। चेतावनी के संकेत तब स्पष्ट हो गए जब अजित ने भाजपा का दामन थाम लिया और सरकार बनाने में अपने चाचा को धोखा दिया।

दुनिया का सिरमौर बनने की ओर अग्रसर भारत

ललित गर्ग

अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत एवं उसके प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की साख एवं सीख के कारण भारत दुनिया का सिरमौर बनने की दिशा में अग्रसर है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में 5 दिन के विदेश दौर में तीन देशों की यात्रा की और 31 ग्लोबल लीडर्स और वैश्विक संगठनों के प्रमुखों के साथ मुलाकात की। मोदी की विदेश यात्राओं से विश्व में भारत का न सिर्फ सम्मान बढ़ रहा है बल्कि दुनिया का हमारे देश के प्रति नजरिया भी बदल रहा है। भारत का हमेशा से मानना रहा है कि दुनिया के शीर्ष ताकतों को सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। आर्थिक रूप से संपन्न देशों को छोटे-छोटे देशों के हितों का भी उतना ही ख्याल रखना होगा। प्रधानमंत्री के एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य का मंत्र इस बात की ओर ही संकेत है। भारत में वैश्विक विकास को फिर से पटरी पर लाने, युद्धमुक्त दुनिया बनाने, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य और डिजिटल परिवर्तन जैसे वैश्विक चिंतों के प्रमुख मुद्दों पर दुनिया की अगुवाई करने की क्षमता है। इस पहलू को अब दुनिया की तमाम बड़ी शक्तियां भी स्वीकार करने लगी हैं। मोदी ने बार-बार कहा है भारत वसुधैव कुटुम्बकम की भावना से काम करता है, जिसमें छोटे-छोटे देशों के हितों को पूरा करने के लिए समान विकास और साझा भविष्य का संदेश भी निहित है, जो भारत की आशावादी एवं समतामूलक सोच को दर्शाता है।

भारत को स्वर्णिम भारत, अच्छा भारत, रामराज्य का भारत या दुनिया का सिरमौर इसलिये कहा जाता है कि यह वो देश है जहाँ से दुनिया ने शून्य को जाना। खेल, पर्यटन और फिल्मों से जिसको पहचाना जाता है। जिसकी अंतरिक्ष में पहुँच, तकनीकी प्रतिभाओं से विश्व ने भी भारत का लोहा माना है। बिना रक्त क्रांति के जितने पायी थी आजादी। भारत दुनिया को बाजार नहीं, एक परिवार मानता है। संतों के सान्निध्य में चलने वाली भारत की व्यवस्था पूरी दुनिया के लिए मार्गदर्शन है। मानव सभ्यता के 95 प्रतिशत समय तक भारत दुनिया को खनिज, मसाले और धातुओं के साथ ही धर्म, गणित एवं खगोलशास्त्र की अवधारणाएं देता रहा। जब सारी दुनिया भटकती है तब भारत उसका मार्ग प्रशस्त करता है। भारत उकराव और संघर्ष को मानवता के लिए खरारा मानता



है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि मौजूदा दौर में हमें अपने अस्तित्व ही नहीं, सम्पूर्ण मानवता के लिए लड़ने की जरूरत है। भारत ने अपनी विदेश नीति के जरिए हमेशा ही ये संदेश दिया है कि आज दुनिया जलवायु परिवर्तन, गरीबी, आतंकवाद, युद्ध और महामारी जैसी जिन सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, उनका समाधान आपस में लड़कर नहीं बल्कि मिलकर काम करके ही निकाला जा सकता है।

आज दुनिया में ऐसी ही संवेदनशील अर्थव्यवस्थाओं के निर्माण की चर्चा हो रही है जहाँ समाज कल्याण एवं जीडीपी विकास दोनों का सह-अस्तित्व हो और नागरिकों की प्रसन्नता सर्वोपरि हो। भारत ऐसी ही अर्थव्यवस्था यानी संवेदनशील वैभव के सदुपयोग को खुशहाल जीवन और दीर्घकालिक आत्मनिर्भर समाज का आधार मानते हुए आगे बढ़ रहा है। भारतीय सभ्यता सदा से धन और दान दोनों को सर्वोच्च मानती है। हमारे ऋषियों-मनीषियों ने वाकपटुता, सहायता करने की तत्परता, शत्रुओं से निपटने की बुद्धिमत्ता, स्मृति, कौशल, नैतिकता एवं राजनीति का ज्ञान आदि गुणों को सफल नेतृत्व का आधार बताया और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इन्हीं गुणों के बल पर भारत को दुनिया में अव्वल स्थान पर पहुंचाया है। भारत के पास सबसे मजबूत लोकतंत्र है, विविधता है, स्वदेशी एवं समावेश सोच, आदर्श जीवनशैली, वैश्विक सोच है और दुनिया इन्हीं आईडिआज में अपनी सभी चुनौतियों का समाधान देख रही है।

आज अमेरिकी अपनी गिरती साख को लेकर चिन्तित है। यूरोपीय संस्कृति ऐसी रही है, जिसमें उन वस्तुओं पर भी पैसा बर्बाद गया, जिनकी उन्हें कभी जरूरत ही नहीं थी।

चीन ने कारोबार और नीतियों का ऐसा रास्ता अपनाया, जिसमें कोई नैतिकता नहीं। रूस अपने शत्रु को आंकने में गलती कर गया और एक अंतहीन से युद्ध में उलझकर रह गया। दुनिया में मची इस उथल-पुथल के बीच ऐसा लगता है कि केवल भारत ही ऐसी प्रमुख शक्ति है, जिसने ऐसा रास्ता चुना जो कूटनीतिक समझ और नैतिकता से भरा है। साथ ही, उसने एक स्थिर अर्थव्यवस्था के वैश्विक ब्रांड के रूप में खुद को स्थापित किया है, जिसके साथ दुनिया व्यापार करना चाहती है। ये सब इसी कारण संभव हुआ, क्योंकि हम अपनी संस्कृति से जुड़े हैं, हमारा नेतृत्व संस्कृति से जुड़ा एक महान् कर्मयोद्धा कर रहा है।

दुनिया पिछले हजारों सालों से सुखों के लिए दौड़ रही है लेकिन इस दौड़ में हार चुकी है। अब उसकी नजर भारत पर है। देश को अपनी सारी शक्ति एकजुट करनी होगी। सारी दुनिया में कड़पंथ और उदारता के बीच लड़ाई चल रही है। कपट और सरलता के बीच संघर्ष चल रहा है। देश को अपने मूल्यों को स्थापित करने के लिए सेनापति की भूमिका निभानी होगी और उसके लिये उसकी तैयारी भी है।

वर्तमान में भारत आर्थिक, सामरिक, वैज्ञानिक तथा ज्ञान के क्षेत्र में विश्व का सिरमौर बन रहा है, यह अच्छा संकेत है। अन्यान्य क्षेत्रों के साथ भारत सौर ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया का सिरमौर है। सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। इसलिए सारा संसार भारत की ओर बड़ी आशा और विश्वास के साथ देख रहा है। परन्तु अनेकानेक विशेषताओं एवं विलक्षणताओं के बीच कुछ विसंगतियां एवं विषमताएं भी हैं। भारत की अस्मिता का प्रतीक मातृशक्ति की आज सर्वत्र अवमानना की जा रही है। चरित्रहीनता, भ्रष्टाचार और संवेदनहीनता से जूझता हुआ हमारा भारतीय समाज भोगवादी संस्कृति का आदी हो चुका है। अपने देश में भारत के हित में विचार करनेवाले, समाज की उन्नति के संबंध में चिंतन करनेवाले लोगों की कमी नहीं है। फिर भी आज देश की व्यवस्था में राष्ट्रभक्तों का अभाव दृष्टता है, संकीर्ण राजनीति एवं सत्ता की दौड़ में मूल्यों को धुंलाने की स्थितियां कमजोर करती हैं। यही कारण है कि संपूर्ण देश में एक असंतोष की भावना दिखाई

देती है। सरकारी यंत्रणाओं के प्रति जनमानस का विश्वास प्रायः लुप्त होता जा रहा है।

शिक्षा के क्षेत्र में नये परचम फहराने वाले युवाओं, घर को संस्कारों से संबंधित करनेवाली नारीशक्ति, संपूर्ण भारत के जीवन को पोषित करनेवाले हमारे अन्नदाता किसान भाइयों तथा खेतों, कारखानों तथा सर्वत्र मजदूरी करनेवाले श्रमिकों, वन-संस्कृति का जतन करनेवाले वनवासी भगिनी-बंधुओं के आत्मविश्वास, लगन तथा परिश्रम के जागरण से भारत दुनिया में अव्वल होने की दिशा में अग्रसर है। देश का शिक्षित, प्रबुद्ध तथा समृद्ध समाज को दीन-दलितों, अशिक्षितों तथा असहाय लोगों के उत्थान के लिए आगे आना होगा। अंतर्राष्ट्रीय संगठन डेल्टाएट ने अपनी हालिया रिपोर्ट में वर्ष 2030 तक भारत के चीन और अमेरिका जैसी विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे बड़े उपभोक्ता बाजार के रूप में उभर कर सामने आने की आशा व्यक्त की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के मध्यम वर्ग का दायरा काफी तेजी से बढ़ रहा है जिसके कारण बाजार तक पहुंच रखने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। व्यापार की नीतियों में उदारीकरण और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ने का असर उपभोक्ता बाजार पर दिख रहा है, सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं और उत्पादों के निर्यात में बढ़ोतरी ने भी उपभोक्ता बाजार का आकार बढ़ाने में सहायता की है।

हमें राष्ट्र को आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक तथा सामरिक दृष्टि से सबल बनाना होगा। भारत को दुनिया का सिरमौर देखने की कामना करने वाले लोगों से अपेक्षा है कि वे जागे, कुछ नया और अनूठा करें। आनेवाली पीढ़ियों तुम्हें निहार रही हैं। भारत का भविष्य अब युवाओं पर ही निर्भर है। उठो, जागो और समस्त दायित्व अपने कंधों पर ले लो। और जान लो कि तुम ही अपने भाग्य के विधाता हो। जितनी शक्ति और सहायता चाहिए वह सब तुम्हारे भीतर है। अतः अपना भविष्य स्वयं गढ़ें। मानव चिंतन के शीर्ष पर रहने वाला भारतीय समाज 300 वर्षों के अंतराल के बाद अपने ऐतिहासिक गौरव को फिर से पाने के पथ पर अग्रसर है। मध्यकाल में राह भटकने के बाद आनंद देश की युवा पीढ़ी एक ऐसे भारत में आगे बढ़ रही है, जो अवसर, संस्कृति और प्रगति का देश है।

पुराण दिग्दर्शन तीसरा अध्याय

वेदों में अष्टादश पुराणों के नाम

गतांक से आगे...

व्यास-कर्तृत्व पर भी मनमाने आक्षेप किया करते हैं। इसलिए इस अध्याय में ऐसे ही आक्षेपों के समाधान करने का प्रयत्न किया जाता है।

श्री पं. ज्वालाप्रसाद जी मिश्र, वेदव्याख्याता पं. भीमसेन शर्मा तथा श्री पं. कालुराम जी शास्त्री आदि स्वामीय महानुभाओं ने अपने लेखों में ऐसे आक्षेपों पर विचार किया है। यद्यपि उनकी विद्यमानता में हमें अधिक कुछ लिखने की आवश्यकता न थी, तथापि पुराण- सम्बन्धी समस्त विचारों से परिपूर्ण इस ग्रन्थ में कर्तृत्व विषय पर सर्वथा मौनवलम्बन करना भी पाठकों को अवश्य खटकता। पूर्वद्वय द्विवेदं सुबुद्धम न्याय के अनुसार कतिपय पंक्तियें लिखी जाती हैं।

आक्षेप और उनका समाधान- (1) वर्तमान पुराणों में बुद्ध का वर्णन आता है। बुद्ध जी लगभग 600 वर्ष विक्रमपूर्व हुए और व्यास जी महाभारतकालीन व्यक्ति हैं। जिसे पांच हजार वर्ष से

अधिक समय हो चुका है। अतः व्यासकृत पुराणों में अपने से परवर्ती व्यक्ति का वर्णन नहीं आ सकता, अवश्य ही ये पुराण बुद्ध के बाद के बने हैं, यह स्पष्ट है।

(2) इस आक्षेप में पुराणों को नवीन सिद्ध करने के लिए व्यास और बुद्ध के समयों का अन्तर कारण रखा गया है। परन्तु वास्तव में यह हेतु कोरा भूत्वाभास है; क्योंकि वेद, पुराण आदि ग्रन्थ केवल हेतुकाल की घटनाओं के प्रतिपादक नहीं हैं। अपितु -भूतं भव्यं भविष्यच्च सर्वं वेदात्प्रसिद्धयति। (मनु: 12।167) अर्थात्- भूत, भविष्यत् वर्तमान, सब कुछ वेद से सिद्ध है- इस मनुकि के अनुसार वेद तीनों काल का वर्णन करने वाले हैं। जिस प्रकार आनादि वेदों में यास्क आदि वेदाचार्यों के निर्णयानुसार वशिष्ठ, विश्वामित्र, गुण:शेष आदि उत्तरकालीन व्यक्तियों का उल्लेख सुव्यवस्थित है।

क्रमशः ...



योगेश कुमार गोयल

प्रतिवर्ष 4 दिसम्बर को भारतीय नौसेना के जांबाजों को याद करते हुए 'भारतीय नौसेना दिवस' मनाया जाता है। यह दिवस 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में भारतीय नौसेना की शानदार जीत के जश्न के रूप में मनाया जाता है। दरअसल 3 दिसम्बर 1971 को पाकिस्तानी सेना ने हमारे हवाई और सीमावर्ती क्षेत्र में हमला कर दिया था। दुष्ट पाकिस्तान को उस हमले का मुहोतड़ जवाब देने के लिए पाकिस्तानी नौसेना के कराची स्थित मुख्यालय को निशाने पर लेकर 'ऑपरेशन ट्राइडेंट' के आक्रमणकारी समूह ने कराची के तट पर जहाजों के समूह पर हमला कर दिया था। हमले में पाकिस्तान के कई जहाज और

'भारतीय नौसेना दिवस'



ऑयल टैंकर तबाह कर दिए गए थे।

भारतीय नौसेना का वह हमला इतना आक्रामक था कि कराची बंदरगाह पूरी तरह बर्बाद हो गया था और कराची तेल डिपो पूरे सात दिनों तक धू-धुकर जलता रहा था। तेल टैंकरों में लगी आग की लपटों को 60 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता था। उस हमले में कराची हार्बर पयूल स्टोरेज तबाह होने के कारण पाकिस्तानी नौसेना की कमर टूट गई थी। भारतीय नौसेना द्वारा किए गए हमले में तीन विद्युत क्लास मिसाइल बोट, दो एंटी-

सबमरीन और एक टैंकर शामिल थे और युद्ध में भारतीय नौसेना ने पहली बार जहाज पर मार करने वाली एंटी शिप मिसाइल से हमला किया था। ऑपरेशन ट्राइडेंट की सफलता के बाद भारत-पाकिस्तान युद्ध में जीत हासिल करने वाली भारतीय नौसेना की शक्ति और बहादुरी की सलाम करने के लिए 4 दिसम्बर को भारतीय नौसेना दिवस मनाने की शुरुआत हुई। नौसेना दिवस हर साल एक खास थीम के साथ मनाया जाता है और 2023 के नौसेना दिवस का विषय है 'समुद्री क्षेत्र में परिचालन दक्षता, तत्परता और मिशन उपलब्धि'। समुद्री क्षेत्र में परिचालन दक्षता, तैयारियों और मिशन की उपलब्धि को बनाए रखने, देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने और समुद्री खतरों के खिलाफ सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय नौसेना के समर्पण पर प्रकाश डालता है।

नौसेना दिवस समारोह में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की योजना विशाखापट्टनम स्थित भारतीय नौसेना कमान द्वारा तैयार की जाती है। समारोह की शुरुआत युद्ध स्मारक पर पुष्प अर्पण करके की जाती है, उसके बाद नौसेना की पनडुब्बियों, जहाजों, विमानों आदि की ताकत और कौशल का प्रदर्शन किया जाता है। नौसेना के मुंबई स्थित मुख्यालय में इस अवसर पर नौसैनिक अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हैं और गेटवे ऑफ इंडिया बीटिंग रीट्टेट सेरेमनी का आयोजन किया जाता है। भारतीय नौसेना मुख्य रूप से तीन भागों (वेस्टर्न नेवल कमांड, ईस्टर्न नेवल कमांड तथा दक्षिणी नेवल कमांड) में बंटी है। वेस्टर्न नेवल कमांड का मुख्यालय मुंबई में है, ईस्टर्न नेवल कमांड का विशाखापट्टनम में और दक्षिणी नेवल कमांड का कोच्चि में है।

अतिवादी बांग्लादेश की नकेल कसें मोदी-ट्रंप

प्रभु चावला

विश्व स्तर पर धार्मिक पदानुक्रम क्या ढह रहा है? एम्स्टर्डम से लेकर पेरिस और लंदन से न्यूयॉर्क तक प्रवासियों की हिंसक भीड़ विभिन्न संस्कृतियों को निशाना बना रही है। बांग्लादेश इसका नया केंद्र है, जहाँ एक नोबेल पुरस्कार विजेता अब सांप्रदायिक हत्याओं के लिए भर्त्सना के पात्र हैं। जब से बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में मोहम्मद यूनुस पश्चिम से ढाका आये हैं, तब से वहाँ अल्पसंख्यक हिंदुओं का ऐसा सफाया हो रहा है, जैसा विभाजन के बाद नहीं हुआ। पश्चिम के इस दुलारे आदमी की सांप्रदायिक सोच छिपी नहीं है। इस्काँन के पूर्व आध्यात्मिक गुरु चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी बताती है कि यूनुस की सांप्रदायिक सोच नहीं बदली है।

मोहम्मद यूनुस को प्रदान किये गये नोबेल पुरस्कार में उनकी प्रशस्ति में लिखा है - 'पृथ्वी के हर व्यक्ति के पास बेहतर जीवन जीने की क्षमता और अधिकार हैं। यूनुस और ग्रामीण बैंक ने यह दिखाया है कि गरीबों में सबसे गरीब आदमी भी अपने विकास के लिए काम कर सकता है।' यूनुस का प्रसंग दिखाता है कि जिस व्यक्ति ने पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग करने के लिए अमेरिका में बांग्लादेश इनफार्मेशन सेंटर की स्थापना कर उसका नेतृत्व किया, वही आदमी पाकिस्तान से अपना समुद्री स्टुट खोलकर आज इसलामाबाद का मोहरा और वाशिंगटन का पिछलगू बन गया है। यूनुस नेल्सन मंडेला द्वारा शुरु किया गया 'द इलडस' के संस्थापक सदस्यों में थे, जिसका उद्देश्य दुनिया की सबसे कठिन समस्याओं से निपटने के लिए हुआ था और जिसमें इनसे इनके ज्ञान, स्वतंत्र नेतृत्व और ईमानदारी की अपेक्षा थी। जबकि विश्व अपने ही देश में उस सांप्रदायिक भेदभाव वाली सोच के मुखिया हैं, जहाँ हर 100 नागरिकों में से आठ सुरक्षित जीवन जीने के अपने अधिकार से वंचित हैं।



पिछले चार महीने में वहाँ अनेक प्रसिद्ध हिंदू और अल्पसंख्यक नेताओं को हास्यास्पद आरोपों में गिरफ्तार किया गया है।

फिर से एकजुट हुए सीआईए-आइएसआइ गठजोड़ के मोहरे यूनुस ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को कभी विराम नहीं दिया। आज बांग्लादेश का नेतृत्व 84 साल का यही व्यक्ति कर रहा है, जिसकी पहचान एक कट्टरवादी उन्मादी की है। उन्होंने बांग्लादेश के पिता और दशकों से उसके मित्र रहे भारत को सबसे घृणास्पद शत्रु में बदल दिया है। यूनुस ने इस तथ्य की अनदेखी कर दी कि बांग्लादेश के विकास के लिए भारत ने 10 अरब डॉलर से ज्यादा की मदद की है। जेहादियों ने इसकी भी अनदेखी की कि बांग्लादेश में बिजली की कुल खपत का 25 प्रतिशत भारत मुहैया कराता है।

मोदी विरोधी, उदारवादी सहयोगी नेटवर्क ने बगैर जिम्मेदारी के यूनुस को अपना अजेंडा चलाने की छूट दे रखी है। शोख हसीना भी निरंकुश थीं। लेकिन यूनुस के नेतृत्व में शोख हसीना के ज्यादातर कैबिनेट मंत्रियों को मार दिया गया है या जेल में डाल दिया गया है। न्यापालिका को भी अपने हिसाब से ढाल लिया गया है। पाकिस्तान परस्त तत्वों का गुप्सा

शोख हसीना से ज्यादा भारत पर केंद्रित दिखा। यूनुस ने खालिदा-जिया समेत अनेक भारत- विरोधियों को जेल से रिहा किया। हिंदू प्रतिरोध को बलपूर्वक कुचल दिया गया। सिंधान के प्रति निष्ठावानों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस्काँन पर प्रतिबंध लगा दिया गया, बावजूद इसके कि इसके पूर्व नेता चिन्मय कृष्ण दास ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा, ' मैं सभी सनातनियों से यह अनुरोध करता हूँ कि बांग्लादेश हमारा प्यारा देश है, और हम इसे छोड़कर जाना नहीं चाहते। हम इसी धरती के पुत्र हैं। हम इस धरती की विरासत और संस्कृति को संरक्षित करना चाहते हैं।' लेकिन उनकी देशभक्ति की अनदेखी कर दी गयी। बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी कार्डसिल ने पांच अगस्त से 2,000 से अधिक हिंदुओं पर हुए हमले का ब्योरा दिया। ऐसे में, अपने यहां मोदी सरकार पर दबाव बढ़ने लगा। संघ परिवार ने युसपैठियों को बाहर करने का अपना अभियान तेज किया। चूँकि राम मंदिर निर्माण, अतृच्छेद 370 हटाने, समान नागरिक संहिता पर आंशिक रूप से अमल तथा शिक्षा नीति में सांस्कृतिक सुधार के उसके तमाम लक्ष्य पूरे हो चुके, इसलिए उन्हें लगा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से आये युसपैठियों को बाहर निकालने का यही समय है। यह नरेंद्र मोदी ही थे, जिन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर युसपैठियों के खिलाफ आंदोलन चलाया था। वर्ष 2014 में अपने चुनावी अभियान के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर युसपैठियों को सुरक्षा देने का आरोप लगाते हुए कहा था, 'प्रधानमंत्री जी, देश जानना चाहता है कि बांग्लादेश से आये अवैध युसपैठियों के बारे में आपकी क्या राय है। आपकी

नीति क्या है? क्या भारत में बांग्लादेशियों का बोलबाला रहेगा?'

युसपैठियों का मामला हाल के चुनावों में भी भाजपा के लिए एक बड़ा मुद्दा रहा है। झारखंड में खुद मोदी ने कहा था, 'बांग्लादेशी और रोहिंग्या युसपैठिये संताल परगना और कोल्हान में बड़ा खतरा बन गये हैं। इस क्षेत्र की जनसांख्यिकी तेजी से बदल रही है। आदिवासियों की आबादी घट रही है। युसपैठिये पंचायती व्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित कर रहे हैं, जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, हमारी बेटियों पर अत्याचार कर रहे हैं।झारखंड का हर नागरिक खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है।' युसपैठियों को वापस भेजने और बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन ही मोदी के हथियार नहीं हैं। आर्थिक प्रतिबंध भी यूनुस को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता है। शोख हसीना के 15 साल के कार्यकाल में भारत उसका सबसे बड़ा विकास भागीदार है। बांग्लादेश को ढांचगत विकास के लिए भारत से आठ अरब डॉलर की क्रेडिट लाइन मिली थी। कोलकाता असंख्य बांग्लादेशियों का घर था। लेकिन हिंदुओं पर हमले के बाद से भारत ने ढाका में अपना वीजा केंद्र बंद कर दिया है। आदिवासियों के लोगों पर प्रतिकूल असर पड़ा है। नरेंद्र मोदी को अपने वैश्विक कद का इस्तेमाल कर सांप्रदायिक बांग्लादेश को अलगा-थलग करना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपने मजबूत रिश्ते के जरिये उन्हें अतिवादी बांग्लादेश को मिल रहा अमेरिकी समर्थन बंद करने की दिशा में सक्रिय होना चाहिए। अपने चुनाव अभियान में ट्रंप ने एक्स पर लिखा था = 'बांग्लादेश में भीड़ ने हिंदुओं को, ईसाइयों व दूसरे अल्पसंख्यकों पर जिस तरह हमले किये और उन्हें लूटा, मैं उसकी तीव्र निंदा करता हूँ।' अब वह मोदी पर है कि भारत के खिलाफ सांप्रदायिक षड्यंत्र करने वालों के विरुद्ध अपनी भी-राजनीतिक शक्ति का प्रयोग कर दूसरे देशों में हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों की रक्षा करें तथा वैश्विक हिंदुत्व के मसीहा बनें।

आज का इतिहास

- 1909 पहला ग्रे कप खेल, कैनेडियनफुटबॉल लीग का चैम्पियनशिप खेल आयोजित किया गया था।
- 1909 दुनिया के सबसे पुराने पेशेवर आइस हॉकी क्लब मॉन्ट्रियल कैनाडीन्स को राष्ट्रीय हॉकीअभियान के चार्टर सदस्य के रूप में स्थापित किया गया था।
- 1937 के फ्रांसिस अधिनीत राजनीतिक नाटक फिल्म फर्स्ट लेडी जारी की गई।
- 1943 वर्ल्स प्रोग्रेस एडमिनिस्ट्रेशन समाप्त हो गया है। इसे 1930 के दशक में ग्रेट ब्रिटेन की अविधि के दौरान रोजगार प्रदान करने के लिए बनाया गया था।
- 1952 लंदन में चार दिनों तक घातक धुंध छा गई है, जिससे लगभग 4000 लोग मारे गए हैं। यह स्पष्ट रूप से घरों में कारखानों, कारों और कोयले की आग से निकलने वाले धुएँ के कालिख और सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा बनाया गया है।
- 1952 इंग्लैंड में स्मॉग की घनी परत के छा जाने के कारण हजारों लोगों की जान चली गई थी।
- 1954 वैश्विक हेमबर्गर फास्ट फूड चेन बर्गर किंग, जिसे व्हिस्पर के आइटम के लिए जाना जाता है, की स्थापना मियामी, फ्लोरिडा, अमेरिका में की गई थी।
- 1955 लक्समबर्ग में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लड डोनर ऑर्गनाइजेशन की स्थापना की गई।
- 1957 लंदन में ल्यूथम रेल दुर्घटना में 92 लोग मारे गए
- 1971 द ट्रॉल्स-द उल्स्टर वॉलंटियर फोर्स, एक उल्स्टर लॉयलिस्टपरिमिलिटरी ग्रुप, उत्तरी आयरलैंड के बेलफास्ट में एक कैथोलिक के स्वामित्व वाले पब में बम विस्फोट किया, जिसमें 15 लोग मारे गए।
- 1979 बूस जॉर्ज पीटर ली ने इंग्लैंड के हल में एक परिवार के घर में आग लगा दी; अपनी गिरफ्तारी के बाद उसने खुलासा किया कि उसने इलाके में नौ अन्य घातक गोलीबारी शुरू की थी।
- 1980 अंग्रेजी रॉक समूह का नेतृत्व जेर्सेलिन ने आधिकारिक तौर पर भंग कर दिया।
- 1984 हिजोबुल्ल हमलावरों ने कुवैत एयरलाइंस विमान को अपहरण किया और 4 यात्रियों को मार दिया।
- 1992 अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज एच। डब्ल्यू। बुश ने सोमालिया में अमेरिकी सैनिकों को मानवीय सहायता प्रदान करने में मदद करने का आदेश दिया।
- 1996 अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मंगल ग्रह के लिए एक और अंतरिक्ष यान मार्स पाथफाइंडर प्रक्षेपित किया।

शिवसेना यूबीटी यदि सूझबूझ दिखाए तो पुनः पलट सकती है सियासी बाजी!

कमलेश पांडे

कभी महाराष्ट्र की सियासी धड़कन समझी जाने वाली शिवसेना भाजपा से अपनी गहरी दोस्ती के लिए जानी मानी जाती थी, लेकिन मुख्यमंत्री पद के सवाल ने दोनों के बीच जो खटास पैदा की, वो निरन्तर जारी है। इसने अवसरवादी प्रवृत्ति ने क्षेत्रीय हिंदूवादी राजनीति को गहरा आघात पहुंचाया है। शिवसेना के पूर्व सुप्रीमो और अब शिवसेना यूबीटी के सर्वेसर्वा तथा महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव भाऊ ठाकरे के बाद जब शिवसेना के नए प्रमुख और महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जब पुनः मुख्यमंत्री पद के सवाल पर पहले सरपेंस और बाद में क्लीनचिट वाली राजनीतिक चाल चली तो राजनीतिक गलियारे में उद्धव ठाकरे के ऊपर लगी पदलोचुपता की दाग धूल गई।

आपको यह जानकर हैरत होगी कि जैसे ही शिवसैनिकों ने एकनाथ शिंदे तक यह खबर पहुंचाई कि यदि वो सियासी फूफा बनने का स्वंग रचेंगे तो भाजपा, शिवसेना यूबीटी के उद्धव ठाकरे के ऊपर डोरे डाल सकती है, वैसे ही एकनाथ शिंदे के होश उड़ गए। क्योंकि शिवसेना यूबीटी द्वारा कांग्रेस की आलोचना किये जाने के पीछे की एक वजह यह भी है। इसके अलावा, एनसीपी प्रमुख अजित पवार के ऊपर भी भाजपा का भरोसा मजबूत होगा और बीजेपी की महाराष्ट्र सरकार आसानी से बन जाएगा। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार पहले भी मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं और गत विधानसभा चुनावों में बंटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे के

दोनों के बीच जो मतभेद पैदा हुआ है, उसे भी पाटने में मदद मिल जाएगी। बता दें कि अजित पवार के गत दिनों के ताजा बयान का संदेश भी स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री भाजपा का ही होगा। इससे पहले एकनाथ भी लगभग यही बात बोल चुके हैं। इसलिए किसी तरह की गलतफहमी न केवल महायुति की सियासी साख बल्कि शिवसेना और एकनाथ शिंदे के राजनीतिक वजूद पर भी सवाल पैदा कर सकते हैं। समझा जाता है कि यही सब सोचकर बीमार एकनाथ रविवार को चंगा हो गए और महायुति की बीजेपी सरकार के पक्ष में सकारात्मक बयानबाजी किए। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस भी यही चाहते थे। उन्हें पता है कि उनके समानांतर किसी को पैदा किया जाता है, इसलिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पर वो शक करते हैं!

सच कहां तो महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन से पहले जो पूरा सियासी ड्रामा मुंबई से दिल्ली तक चला, इससे यदि किसी को लाभ मिल सकता है तो वह है शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे। क्योंकि बीएमसी चुनाव सिर पर है। जब उन्हें यह पता चल चुका है कि कांग्रेस उनको ज्यादा तवज्जो नहीं देगी, तब वह अपने मूल जनाधार को बचाने की रणनीति बनाएँ, जो उनकी गलत नीतियों के चलते एकनाथ शिंदे की तरफ शिफ्ट होते दिखाई पड़ रहे हैं। इसके लिए वह भाजपा की सरकार को बाहर से समर्थन देने की पहल करें, वो भी बिना मांगें। इससे भाजपा से ज्यादा शिवसैनिकों की सहानुभूति उन्हें मिलेगी।

इसके बाद वह महाराष्ट्र से बाहर निकलें और पूरे देश



में हिंदूवादी राजनीति को मजबूत करें। क्योंकि सत्ता में रहकर भाजपा जो काम नहीं कर सकती है, वह उनकी परोक्ष सहयोगी बनकर शिवसेना यूबीटी कर सकती है, क्योंकि सिर्फ शिवसेना गई है, उसका मुख पत्र सामना (दोपहर का सामना) आज भी उनके पास है। पहले उद्धव इसका देश व्यापी विस्तार करें और फिर उसी की आड़ में सियासी गोटियां सेंट करें। क्योंकि देर सबेर शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे और एनसीपी प्रमुख अजित पवार भाजपा से दूर जाएंगे, क्योंकि इनकी सियासी तासीर कभी देवेंद्र फडणवीस से मेल नहीं खाएगी। इसलिए शिवसेना यूबीटी यदि राजनीतिक

सूझबूझ दिखाएगी, तो उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे दोनों का भविष्य उज्वल रहेगा। राजनीतिक रूप से देखें तो चाहे केंद्र की एनडीए सरकार हो या महाराष्ट्र की महायुति सरकार, शिवसेना यूटीबी की जरूरत भाजपा को पड़ेगी ही, ताकि वह अपने सहयोगियों पर प्रेशर की राजनीति डाल सके। यह मोदी-शाह का सियासी स्वभाव है। वहीं, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर महाराष्ट्र के कार्यवाहक उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जैसे बीजेपी की तीसरी पीढ़ी के नेताओं को अपने व्यक्तिगत विस्तार और संरक्षण के

लिए भी शिवसेना की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि उद्धव को पता होना चाहिए कि बड़े दलों में भी देवेंद्र फडणवीस जैसे जमीनी नेता इसलिए अपना वजूद कायम रख पाते हैं, क्योंकि वह समय के साथ बदलते रहते हैं। इसलिए उद्धव ठाकरे भी सियासी हठ छोड़ें और राजनीतिक सूझबूझ भरा फैसला लें। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने के लिए कांग्रेस का साथ लेना उनकी गलत रणनीति नहीं थी, बशर्त कि वह उससे खुद को महाराष्ट्र का नेता मनवा लें। लेकिन जब ऐसा नहीं कर सके, तो अब घर वापसी की जुगत बिटाएँ। खुद को बीएमसी चुनाव में मजबूत करें। महाराष्ट्र में शिवसैनिकों के विश्वास पुनः जीतें! क्योंकि राजनीतिक मौतें हमेशा अस्थायी होती हैं, शाश्वत तो नेताओं व उनके दलों की नीतियां होती हैं, जो उन्हें बार बार राजनीतिक पुनर्जन्म देती हैं। बिहार के जदयू नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से यदि वह सियासी ज्ञान लेते रहें तो घरवापसी भी ज्यादा कशमकश वाली नहीं रह जायेगी। पते की बात तो यह होगी कि भाजपा जिन हिंदूवादी मुद्दे पर मुखर होकर नहीं बोल पाती है, वह उसपर मुखर हों। संघ से देशव्यापी आशीर्वाद की कामना करें, क्योंकि भाजपा पर सियासी अंकुश रखने के लिए भी संघ को शिवसेना जैसे पुराने शुभचिंतकों की जरूरत हमेशा पड़ेगी। देश के 1800 मंदिरों के जीर्णोद्धार का मुद्दा सबसे अहम है, इसलिए इन्हें उठाकर भी शिवसेना यूटीबी अपना खोया राजनीतिक वजूद फिर से पा सकती है। बस, धैर्य व विनम्रता पूर्वक उद्धव आगे बढ़ें, आदित्य को आगे बढ़ाएँ।

ईवीएम को लेकर विपक्षी दलों का रवेया 'चित भी मेरी, पट भी मेरी'?

अमेश चतुर्वेदी

पिछले कुछ साल से ईवीएम को लेकर विपक्षी दलों का रवेया 'चित भी मेरी, पट भी मेरी' कहावत की तरह है। अब ईवीएम विरोधी राग में अपना सुर उस कांग्रेस का नेतृत्व भी मिलाने लगा है, जिसके राज में ईवीएम के जरिये चुनाव होना शुरू हुआ। 2009 के आम चुनाव में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल शुरू हुआ। यह बताते की जरूरत नहीं कि उस चुनाव में 2004 की तुलना में कांग्रेस की अगुआई वाले राष्ट्रीय प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए को बड़ी जीत हासिल हुई थी। तब ईवीएम पर भाजपा के तत्कालीन थिंक टैंक के कुछ लोगों ने कुछ वैसा ही आरोप लगाया था, जैसा आरोप आज कांग्रेस समेत समूचा विपक्ष लगा रहा है। ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग को लेकर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर दबाव बनाने को लेकर देशव्यापी यात्रा करने की बात कांग्रेस सोच रही है। महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनावों के बाद हुई कांग्रेस कार्यसमिति की पहली बैठक में कांग्रेस की महासचिव और नवनिर्वाचित सांसद प्रियंका गांधी ने जिस तरह ईवीएम का विरोध किया, उससे लगता है कि कांग्रेस ईवीएम को चुनाव प्रक्रिया से हटाने के लिए आखिरी लड़ाई लड़ने का मूड बना चुकी है। कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में प्रियंका ने कहा कि हमें यह तय करना होगा कि बैलेट पेपर ही चुनाव का एकमात्र रास्ता है, कोई भी का रास्ता नहीं है। अगर राहुल गांधी की सहमति मिली, जिसकी संभावना ज्यादा है, तो तय है कि कांग्रेस ईवीएम के सवाल पर देशव्यापी अभियान पर निकल सकती है। ईवीएम विरोधी नेटिव में कांग्रेस का मददगार प्रगतिशील वामपंथी वैचारिक खेमा बड़ा सहयोगी है। आम मददाता और नागरिक विपक्षी हार के पीछे ईवीएम केंद्रित षड्यंत्र को स्वीकार नहीं कर पा रहा। ईवीएम विरोधी मानस बनाने की कोशिश केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार के स्थापित होने के बाद शुरू हुई। दिलचस्प यह है कि मोदी के उभार के बाद ही कांग्रेस और उसका साथी विपक्ष मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, पंजाब, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर और झारखंड की विधानसभाओं में जीत हासिल कर चुका है। ईवीएम विरोधी नेटिव की शुरुआत के बाद पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी दो-दो, दिल्ली में केजरीवाल दो-दो चुनाव जीत चुके हैं और बिहार में 2015 का चुनाव भी भाजपा विरोधी खेमा जीत चुका है। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा बहुमत के आंकड़े से तैंतीस सीटें पीछे रह गई। ईवीएम विरोधियों के लिए लोगों को यह समझाना आसान नहीं लग रहा कि ईवीएम का अपने लिए इस्तेमाल करने वाली भाजपा आखिर खुद क्यों बहुमत से दूर हो गई? दरअसल इन्हें तथ्यों की बुनियाद वह पेंच है, जिसकी वजह से ईवीएम विरोधी राष्ट्यापी व्यापक माहौल नहीं बन पा रहा है। अदालत को भी इस नेटिव को बढ़ावा देने की राह का सहभागी बनाने का प्रयास हुआ। महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजों के बाद ईवीएम के खिलाफ देश की सबसे बड़ी अदालत में याचिका दायर कर दी गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे न सिर्फ खारिज कर दिया, बल्कि यह भी कहा कि ईवीएम से जब विपक्ष जीतता है तो सवाल क्यों नहीं उठते। एक तरह से अदालत इस प्रक्रिया में भागीदार बनने से इनकार कर चुकी है।

सामंती सोच में बदल रहा दुनिया का लोकतंत्र?

राजेश बादल

संसार के अनेक छोटे-बड़े मुल्कों में अब सामूहिक नेतृत्व का नजरिया विलुप्त हो रहा है। लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचन के बाद चुने गए राष्ट्रप्रमुख अपनी कार्यशैली से राजशाही की याद दिलाते दिखाई देते हैं। खेद की बात है कि सभ्य और साक्षर राष्ट्रों के निवासी अपने तंत्र में आ रही इस खराबी पर चुपचाप हैं। वे अब अपने लोकातांत्रिक अधिकारों के लिए नहीं लड़ते, बल्कि उसी व्यवस्था का हिस्सा बन जाते हैं, जिस सामंती तंत्र को उनके देश सदियों पहले पीछे छोड़ आए हैं। अमेरिका हो या रूस, चीन हो या पाकिस्तान या फिर दुनिया के नक्शे में सिर्फ 53 साल पहले वजूद में आया बांग्लादेश। पहले बात पड़ोसी बांग्लादेश की। वहां निर्वाचित शेख हसीना वाजेद की सरकार को एक गिरोह ने षड्यंत्रपूर्वक अपदस्थ कर दिया। शेख हसीना को जान बचाकर भारत में शरण लेनी पड़ी। इसके बाद इस हुजूम ने नए मुखिया के रूप में मोहम्मद यूनुस को चुन लिया। एकबारगी हम मान लेते हैं कि शेख हसीना के प्रति अवाम में नाराजगी थी तो व्यवस्था कहीं है कि नए चुनाव कराए जाएं और उसमें लोग अपनी सरकार को उखाड़ फेंकें। यह नहीं हुआ। इसके बाद अंतरिम मुख्य सलाहकार के रूप में तख्तापलट करने वालों ने जिसे चुना, उसका पहला कर्तव्य यही था कि संसद भंग करके नए चुनाव कराए जाते। लेकिन यह अंतरिम सरकार जिस ढंग से काम कर रही है, वह तो निर्वाचित सरकार के कामकाज को भी मात देने वाली है।



बिना जनादेश लिए अंतरिम सरकार ऐसे-ऐसे निर्णय ले रही है, जिन्हें लेने के लिए चुनी गई सरकार को भी पापड़ बेनगने पड़ें। हैरत की बात है कि बांग्लादेश की जनता में देश के संवैधानिक चरित्र के खिलाफ काम करने वाली हुकुमत के प्रति कोई गुस्सा नहीं है। जिस पाकिस्तान ने करोड़ों बांग्लादेशियों पर क़र्र और अमानवीय जुल्म ढाए, अब सत्ता में बैठ जायता उसी के इशारे पर नाच रहा है। अर्थ यह कि गलत और अनैतिक तंत्र के रंग में आम आदमी भी रंगा दिखाई दे रहा है। यह कठपुतली सरकार संविधान बदलना चाहती है, अल्पसंख्यकों के हक कुचलना चाहती है और सारे लोकातांत्रिक प्रतीकों को नष्ट करना चाहती है। यहां तक कि अपने राष्ट्राती को इसलिए बदलना चाहती है क्योंकि उसे एक हिंदू अर्थतंत्र गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। जिस बांग्ला भाषा के आधार पर उसका गठन हुआ, उसकी पहचान ही समाप्त करने की पहल हो रही है। एक तरह से पाकिस्तान का इतिहास दोहराया जा रहा है। वहां का पहला राष्ट्राती हिंदू शायर जगन्नाथ आजाद ने लिखा था लेकिन उसे बदलकर हफीज जालंधरी का लिखा राष्ट्राती स्वीकार किया

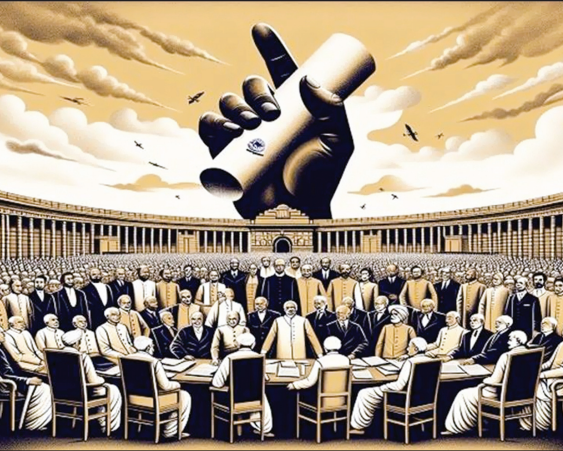
गया। उस दौर के पाकिस्तान में जो घटा था, बांग्लादेश में वही दोहराया जा रहा है। विश्वमंच पर प्रकटे नए नवेले राष्ट्र के बाद आते हैं स्वयंभू चौधरी अमेरिका पर। जब से वहां राष्ट्रपति चुनाव हुआ है और सत्तारूढ़ पार्टी को हार मिली है, तब से मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन बौखलाहट में वह कर रहे हैं, जो लोकतंत्र में पराजित प्रतिनिधि को नहीं करना चाहिए। यह लोकतंत्र का मान्य सिद्धांत है कि चुनाव में पराजय के बाद विजेता के पदभार संभालने तक हारी पार्टी कामचलाऊ सरकार की तरह ही काम करती है। नैतिक और वैध आधार उसे महत्वपूर्ण तथा नीतिगत निर्णय लेने से रोकता है। मगर बाइडेन ऐसे संवेदनशील निर्णय ले रहे हैं, जो आने वाली सरकार के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। यह फैसले रक्षा और विदेश मामलों से जुड़े हुए हैं। अगले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने प्रचार अभियान के दरम्यान रूस-यूक्रेन के बीच जंग एक दिन में रोकने का ऐलान किया था। ट्रम्प सीधे-सीधे रूस का पक्ष ले रहे हैं। इसके बाद भी जो बाइडेन ने यूक्रेन को आर्मी टेक्टिकल तंत्र और उसकी भारी मिसाइलों का उपयोग कर रूस की सीमा में मार करने की अनुमति दे दी। अब अमेरिकी अवाग और ट्रम्प ठगे से देख रहे हैं। यह लोकतंत्र की हार नहीं तो और क्या है? इसी कड़ी में आप यूक्रेन को शामिल कर सकते हैं। यह मेरी राय है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जानबूझकर अपने देश को जंग की आग में झुलसने के लिए मजबूर किया है। यह वैसा ही है कि यदि पाकिस्तान अपनी सीमा पर चीन को सेनाओं को तैनात

करने की इजाजत दे दे तो भारत क्या करेगा? हाल यह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति गद्दी नहीं छोड़ना चाहते। उनका कार्यकाल छह महीने पहले समाप्त हो चुका है, लेकिन जंग के नाम पर वे चुनाव कराने को तैयार नहीं हैं। एक सर्वेक्षण के मुताबिक पूरे यूक्रेन की जनता नया राष्ट्रपति चाहती है, जो युद्ध खत्म कराए। जेलेंस्की पद नहीं छोड़ना चाहते। राष्ट्रपति बनने से पहले वे मिमिक्री कलाकार रहे हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद भी वे देश से मसखरों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। वे कहते हैं कि जब तक देश में मार्शल लाॅ लगना है, तब तक पद से कैसे हटें? दिलचस्प यह कि मार्शल लाॅ लगाने का आदेश भी उन्होंने ही जारी किया था। जेलेंस्की संविधान का ही पालन नहीं कर रहे हैं। यह लोकतंत्र का मखौल नहीं तो और क्या है। दूसरी ओर रूसी राष्ट्रपति इसी जंग के दौरान देश में चुनाव करा चुके हैं। यह अलग बात है कि रूसी राष्ट्रपति के तौर-तरीके सब जानते हैं। उन्हें हटाने वाला कोई नहीं है। फिर भी उन्होंने चुनाव तो कराए ही। अमेरिका के पिछलग्गू यूरोप के देश भी हैरान हैं। अमेरिका के आगे दुग हिलाने के अलावा उनकी कोई नीति नहीं है। क्या यह अटपटा नहीं लगता कि जिस अमेरिका के इशारे पर वे आज यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रम्प के आने पर वे रूस के समर्थन में आ जाएंगे। ऐसे में क्या वे अपने मुल्क के मतदाताओं के साथ धोखा नहीं करेंगे? कमोबेश यही हाल चीन का है। शी जिनपिंग तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए। उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार ही नहीं था। यह चीनी लोकतंत्र है।

संविधान दिवस मनाना महज एक औपचारिकता बना संभल जैसे मामलों में फैसला अदालतों से हो

योगेन्द्र योगी

26 नवंबर, 1949 को भारत का संविधान पारित किया गया और अपनाया गया। इस दिन को संविधान दिवस या राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में जाना जाता है। डॉ.भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि भारत का संविधान व्यावहारिक, लचीला, और मजबूत है। संविधान में हर समस्या का समाधान है। संविधान भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है। इसके बावजूद आजादी के बाद से केंद्र हो या राज्यों की सरकारें, सभी ने संविधान में मौजूद कानूनों को अपने राजनीतिक फायदों के लिए इस्तेमाल करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। राजनीतिक दलों की सत्ता लोलुपता के कारण संविधान काभी हद तक कानून का पुलिंदा बनकर रह गया। राजनीतिक दलों की मनमानी का आलम यह है कि देश आज भी गरीबी, असमानता, अपराध, जनसंख्या बढ़ौतरी, पर्यावरणीय समस्या और बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहा है। संविधान का दुरुपयोग केंद्र में हर दल की सरकार ने करने की भरसक कोशिश की है। इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता बचाने के लिए देश में आपातकाल लगा दिया। संविधान की संरामा धर्मियां उड़ाने का ऐसा मंजर भारत में कभी देखने को नहीं मिला। केंद्र में लम्बे असें तक शासन में रही कांग्रेस की सरकार ने संविधान के दुरुपयोग में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। राज्यों की सरकारों को बर्खास्त करने के लिए आर्टिकल 356 का जमकर दुरुपयोग किया गया। इंदिरा गांधी ने आर्टिकल 356 का 50 बार दुरुपयोग किया। श्रीमती गांधी ने विपक्षी और क्षेत्रीय दलों की सरकारों को गिरा दिया। केरल में वामपंथी सरकार चुनी गई जिसे नेहरू पसंद नहीं करते थे, उसे गिरा दिया गया। करुणानिधि जैसे दिग्गजों की सरकारें गिरा दी गईं। कुल 90 बार चुनी हुई सरकारों को गिराया गया। कांग्रेस सरकार ने डी.एम.के. और वामपंथी सरकारों को गिराया। बदनीयती से संविधान के कानूनों को अपनी सुविधा के हिसाब से बदलने और लागू करने का काम सिर्फ कांग्रेस ने ही नहीं किया, बल्कि केंद्र में शासन में आने के बाद भाजपा भी इसमें पीछे नहीं रही। सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में संविधान के 99वें संशोधन और राष्ट्रीय न्यायिक



नियुक्ति आयोग (एन.जे.ए.सी.) अधिनियम को असंवैधानिक करार देते हुए इसे निरस्त कर दिया और उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए पुरानी कॉलेजियम प्रणाली को बहाल कर दिया। देश के लोगों की सोशल मीडिया के जरिए अभिव्यक्ति और असहमति के अधिकार को केंद्र और राज्यों द्वारा कुचलने की कोशिश को सुप्रीमकोर्ट ने नाकाम कर दिया। सुप्रीमकोर्ट ने आई.टी. एफ्ट की धारा 66ए को असंवैधानिक करार दिया।अदालत ने सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों और गृह सचिवों को यह सुनिश्चित करने के लिए कई निर्देश जारी किए कि सभी लांबित मामलों से धारा 66ए का संदर्भ हटा दिया जाए। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि प्रकाशित आई.टी. अधिनियम के बेयरएक्ट्स को पाठकों को पर्याप्त रूप से सूचित करना चाहिए कि धारा 66ए को अमान्य कर दिया गया है। इस धारा में यह प्रावधान था कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक, उत्तेजक या भ्रानाएँ भड़काने वाली सामग्री डालने पर व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन शीर्ष अदालत ने इस कानून को संविधान के अनुच्छेद 19.1ए के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी के मौलिक अधिकार के खिलाफ बताकर निरस्त कर दिया था। आरक्षण को लेकर सभी राजनीतिक दल वोटों की राजनीति करते रहे हैं। आरक्षण के सही प्रावधानों को लागू करने में भी नेताओं को वोटों का डर सताता

रहा है। यही वजह रही है कि आरक्षण के फायदे-नुकसान पर कोई दल किसी तरह की चर्चा तक करने को तैयार नहीं होता। आरक्षण को लेकर राजनीतिक दलों ने संविधान से छेड़छाड़ करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई.चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की बेंच ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के कोटे में कोटा दिए जाने को मंजूरी दी थी। उस दौरान कोर्ट ने कहा था कि एस्.सी.-एस्.टी. कैटेगरी के भीतर नई सब कैटेगरी बना सकते हैं और इसके तहत अति पिछड़े तबके को अलग से रिजर्वेशन दे सकते हैं। इसको लेकर पी.एम. नरेंद्र मोदी से संसद भवन में 100 दलित सांसद मिले। इसके बाद केंद्र ने इसकी घोषणा भी कर दी कि जरूरत पड़ी तो संसद में विधेयक लाया जाएगा, पर आरक्षण के मौजूदा प्रावधानों में कोई बदलाव मंजूर नहीं होगा। हालांकि तमिलनाडु और कर्नाटक ने सुप्रीमकोर्ट के कोटे में कोटा के निर्णय पर अमल का फैसला किया। इतना ही नहीं, संविधान से इनर जाकर राज्यों की सरकारों ने भी वोटों की राजनीति के लिए आरक्षण को हथियार बनाने के प्रयासों में कसर बाकी नहीं रखी। हां, कुछ राज्यों ने निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण देने का कानून बनाने की कोशिश की है। हालांकि, इन कोशिशों को संवैधानिक चुनौतियों का सामना करना पड़। साल 2008 में महाराष्ट्र सरकार ने भूमिपुत्रों को 80 प्रतिशत आरक्षण देने की कोशिश की थी। केंद्र के साथ राज्यों के भी कानूनों से खिलवाड़ करने के ढेरों उदाहरण मौजूद हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश में अपराधी और माफिया का दबदबा इसके उदाहरण हैं। राजनीतिक दलों ने कानून को शर्मसार करते हुए अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया है। संविधान के कानूनों का जब तक निष्पक्षता से पालन नहीं किया जाएगा तब तक संविधान दिवस जैसे प्रयास देश की मौजूदा समस्याओं के समक्ष मुंह चढ़ाने जैसे ही रहेंगे। संविधान दिवस मनाना महज एक रस्मी रिवाजत रह गई है।

अवधेश कुमार

देश में असहज वातावरण बना हुआ है। काशी-मथुरा से लेकर संभल और अजमेर तक उठे मुद्दों ने ऐसी तस्वीर पेश की है मानो केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकारों की शह पर हिंदूओं का बहुत बड़ा समूह ज्यादा से ज्यादा मस्जिदों को ध्वस्त कर हिंदू स्थलों के निर्माण की तैयारी के लिए आगे बढ़ चुका है। क्या वाकई सच यही है? इसका उत्तर है, नहीं। इस समय आरएसएस प्रमुख डॉ. मोहान भागवत का 2 जून, 2022 को नागपुर में दिया गया वक्तव्य याद किया जा रहा है। उन्होंने कहा था कि अयोध्या, काशी और मथुरा की मान्यता रही है, लेकिन हर मस्जिद में मंदिर क्यों तलाशें? तब परंपरागत संघ विरोधियों ने उनके बयान को पाखंड व ज्यादातर मुस्लिम नेताओं ने आंखों में धूल झोंकना बताया था। आज वही लोग जगह-जगह भागवत की पंक्तियों को उद्धृत कर पूछ रहे हैं कि फिर ऐसा क्यों हो रहा है? संघ विरोधियों की तरफ से ऐसी प्रतिक्रिया आएगी ही, लेकिन संघ को समझने वाले जानते हैं कि भागवत के बयान के बाद कोई स्वयंसेवक ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि संघ या हिंदू समाज के अंदर अपने प्राचीन धार्मिक स्थलों की वापसी की कामना नहीं है। यह ऐतिहासिक सच है कि इस्लामी आक्रमणकारियों और शासकों ने यहां कई धर्मस्थलों को ध्वस्त किया और उनकी जगह मस्जिद या अन्य इस्लामी भवन निर्मित हुए। मुसलमानों के बीच भी इसे स्वीकार करने वाले लोग हैं। लेकिन सवाल है कि इसका समाधान क्या है? क्या हर जगह ऐसे स्थलों को अदालत में ले जाना जरूरी है? संघ ही नहीं, कई लोगों को भी लगता है कि धर्मस्थल वापस मिलने चाहिए। समस्या यह है कि भारत में ऐसे हजारों स्थान हैं। जिस संगठन को दूरगामी हिंदू राष्ट्र के लक्ष्य, लेकिन सवाल है कि इसका समाधान क्या है? क्या हर जगह ऐसे स्थलों को अदालत में ले जाना जरूरी है? संघ ही नहीं, कई लोगों को भी लगता है कि धर्मस्थल वापस मिलने चाहिए। समस्या यह है कि भारत में ऐसे हजारों स्थान हैं। जिस संगठन को दूरगामी हिंदू राष्ट्र के लक्ष्य, लेकिन सवाल है कि इसका समाधान क्या है? क्या हर जगह ऐसे स्थलों को अदालत में ले जाना जरूरी है? संघ ही नहीं, कई लोगों को भी लगता है कि धर्मस्थल वापस मिलने चाहिए। समस्या यह है कि भारत में ऐसे हजारों स्थान हैं। जिस संगठन को दूरगामी हिंदू राष्ट्र के लक्ष्य, लेकिन सवाल है कि इसका समाधान क्या है? क्या हर जगह ऐसे स्थलों को अदालत में ले जाना जरूरी है? संघ ही नहीं, कई लोगों को भी लगता है कि धर्मस्थल वापस मिलने चाहिए। समस्या यह है कि भारत में ऐसे हजारों स्थान हैं। जिस संगठन को दूरगामी हिंदू राष्ट्र के लक्ष्य, लेकिन सवाल है कि इसका समाधान क्या है? क्या हर जगह ऐसे स्थलों को अदालत में ले जाना जरूरी है? संघ ही नहीं, कई लोगों को भी लगता है कि धर्मस्थल वापस मिलने चाहिए। समस्या यह है कि भारत में ऐसे हजारों स्थान हैं। जिस संगठन को दूरगामी हिंदू राष्ट्र के लक्ष्य, लेकिन सवाल है कि इसका समाधान क्या है? क्या हर जगह ऐसे स्थलों को अदालत में ले जाना जरूरी है? संघ ही नहीं, कई लोगों को भी लगता है कि धर्मस्थल वापस मिलने चाहिए।

मामला है तो न्याय, संविधान और कानून की परिधि में रहकर संघर्ष करना चाहिए। हमारी चिंता वर्तमान विश्व में बढ़ती जटिलताएं और भारत की आंतरिक शांति, एकता, अखंडता और विकास है। भाजपा और संघ को लेकर लंबे समय से दुष्प्रचार किया जा रहा है। अतिवादी पक्षों ने मुसलमानों के एक बड़े समूह के अंदर यह गलत जानकारी घर कर दी है कि खतरा सीधे मजहब और वज्यू पर है। बड़े-बड़े मजहबी, राजनीतिक नेता और इस्लामी विद्वान अगर झूठ बोलते हैं कि उनकी मस्जिदें छीनी जा रही हैं, मरसे तोड़े जा रहे हैं तो इसका सीधा असर होता है। सच यह है कि भारत में किसी भी मजहब या संप्रदाय का स्थल बिना न्यायिक आदेश के परिवर्तित हो ही नहीं सकता और न हुआ है। ये मामले इसलिए भी जटिल हो गए क्योंकि आजादी के बाद किसी भी सरकार ने समाधान का प्रयास नहीं किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, डॉ. राजेंद्र प्रसाद आदि की पहल पर जिस तरह की कोशिश सोमनाथ मंदिर के लिए हुई, वैसी दूसरी जगहों के लिए भी हो सकती थी। सच कहां तो विधान के बावजूद सरकारों ने मुस्लिम समुदाय से जुड़े मामलों को छूने से परहेज किया। सरकारों के इस रवेये के खिलाफ लोगों में गुस्सा जनपत रहा। पासदी देखिए कि हिंदूओं की ओर से वास्तविक विवाद उठाने पर संतुलित समाधान की जगह उन्हें खलनायक और दोषी करार दिया जा रहा है। मंदिर-मस्जिद विवाद को बिना किसी गंभीरता के अदालत में उठाने वालों से ज्यादा घातक रवेया उठी लोगों का है, जो हिंदुत्व समर्थकों को किसी भी तरह से बस कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। अगर कोई गैर-भाजपाई नेता संभल में हुई एकपक्षीय हिंसा पर नहीं बोल रहा, तो इसे क्या कहा जाएगा। सोचना होगा कि इस समय भारत के अंदर और बाहर जो परिस्थितियां हैं, उनमें हमारी प्राथमिकता क्या हो? कुछ स्थलों को न्यायिक विवादों में ले जाने से समाधान हो जाए तो इसका समर्थन किया जा सकता है। न भूलें कि ऐसे कदमों से मुसलमानों के अंदर एक समूह को भी अपने कटघरपंथियों के दबाव में आकर या तो चुप रहना पड़ता है या फिर इस झूठ का समर्थन कि संपूर्ण इस्लाम और इस्लामी स्थलों को खत्म करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। फिर क्या सभी मंदिर-मस्जिद विवादों के स्थायी निपटारे के लिए भारत की आंतरिक तैयारी है? क्या ऐसे सारे मामलों का समाधान भी संभव है? संघ प्रमुख की सोच में ये सवाल निहित थे।

फैशन में नए एक्सपेरिमेंट करते रहें



- ▶ टी-शर्ट थिन स्लोगन : युवावस्था में अपना एटीट्यूट खुलकर सामने ला सकते हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका है, 80 के स्टाइल की ब्राइट कलर की स्लोगन लिखी टी-शर्ट पहने। टी-शर्ट पर किसी भी तरह की आर्ट दर्शाई जा सकती है। चाहे वह आपका फेवरिट सुपर हीरो हो या वह साइन जो आपके दिमाग में है।
- ▶ बेसबॉल कैप्स : कॉलेज में ज्यादातर सब ही लड़के केप पहने हुए देखे जा सकते हैं। बेसबॉल कैप्स 90 के दशक में चर्चित हुई थी और अभी भी ट्रेंड में है। वह परफेक्ट एसेसरीज हैं और जींस और टी-शर्ट के साथ पहनी जा सकती है।
- ▶ स्कार्फ़ : मोटे निटिड वाली से लेकर ब्राइट रंग और पैटर्न वाले स्कार्फ़ हर बॉर्डरों में जरूर होने चाहिए। यह वेस्ट पर्न या ब्रेसलेट की तरह हाथ पर बंधे हुए बहुत अच्छे लगते हैं।
- ▶ जैक ज्वेलरी : सड़क के किनारे हंगी दुकानों पर आप थोड़ी बारगेनिंग में आपको पसंदीदा ज्वेलरी मिल जाएगी। आजकल ऐसे ब्राइट रंग के स्टोस और नकली छायमंड रिंग भी पॉपुलर होती जा रही है। बीइस भी टोन फैशन से कभी बाहर नहीं होते। आजकल ज्वेलरी पहनने में लड़के भी पीछे नहीं हैं। उन्हें एक बड़ा सिल्वर पेडेंट या एक कान में इयरिंग पहनना अच्छा लगता है।
- ▶ पोलका डॉट्स : पोलका डॉट्स कभी भी आउट ऑफ़ स्टाइल नहीं जाते। लड़कियां एक वेल् फिटिड पोलका डॉट ड्रेस हील्स के साथ पहन सकती हैं। यह यलो और ग्रीन कलर में बहुत ही फंकी लुक देते हैं। आप कॉलेज के लिए एक लॉन्ग पोलका डॉट टॉप लैमिन्स और पलेट्स के साथ पहन सकती हैं।
- ▶ बेल्ट्स : लंबी, छोटी, पतली, मोटी और सॉलिड रंगों में एम्बेलिशमेंट वाली बेल्ट हर टोन के बॉर्डरों का एक अहम हिस्सा होती है। बेल्ट अब बस पेट या जींस के ऊपर रखने के लिए नहीं होती, बल्कि अब यह ड्रेसिंग, लॉन्ग टी-शर्ट और टयुनिक्स के ऊपर भी पहनी जा सकती है।
- ▶ मोबाइल फोन : लेटेस्ट मॉडल होने के साथ-साथ उसके साथ सही एसेसरीज होना भी जरूरी है। मोबाइल केस, स्टिकर्स, मोबाइल हेमिंग्स सब फोन की पर्सनैलिटी बढ़ाते हैं।

टीनेज की उम्र में हर कोई फैशन की तरफ अट्रैक्ट होता है। इस उम्र में आमतौर पर युवा कुछ न कुछ नए एक्सपेरिमेंट करना पसंद करते हैं। इस उम्र में आप अपनी पर्सनैलिटी और एटिट्यूट अपनी ड्रेसिंग और एसेसरीज से एक्सप्रेस कर सकते हैं।



बच्चों में भी फैशन का क्रेज



फैशन की दौड़ में जब सारी दुनिया दीवानी हो रही है, तो भला बच्चे कैसे पीछे रह सकते हैं। बच्चों में भी अब फैशन का क्रेज आजकल हर जगह देखने को मिलता है, बच्चे जो स्वयं को कैसे फैशन के अनुसार ढालना चाहते हैं, इसे देखकर कभी-कभी फैशनबल माता-पिता भी हेरत में पड़ जाते हैं। घर, स्कूल या पार्टी हो, सजी जगह बच्चे जमाने की चाल में चलना पसंद करते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। मां-बाप भी फैशन के प्रति जागरूक होते जा रहे हैं, जो बच्चों को मेडिंग में रखना ही पसंद करते हैं, जैसे ड्रेस वैसे मोजे, जूते, रूमाल वगैरह-वगैरह।

खिलौने और गेम्स

नए खिलौने, गेम्स जो भी प्रचलन में होते हैं, बच्चों की फरमाइश पर हाजिर हो जाते हैं। जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं, तब भी फैशन के बैग, कम्पास, पेंसिल, रबर लाकर ही दिए जाते हैं। उनके पास नहीं भी होते हैं, तो वे अपने दोस्तों के पास देखकर आकर्षित होते हैं और नई-नई चीजें लाने की मांग करते हैं। समय के साथ चलती यह जागरूकता ही कहे जाएं जिससे वे स्वयं को अलग सा दिखाना चाहते हैं और अपने को नए रूप में स्थापित करना चाहते हैं। सबके आकर्षण का केंद्र बन सकें, दोस्तों के दिल में समां सकें, शिक्षकों व रिश्तेदारों की प्रशंसा पा सकें, इसलिए वे जमाने के नित नए फैशन को अपनाना चाहते हैं।

नए फैशन के मुरीद

वे सोचते हैं कि वर्तमान में जो फैशन चल रहा है, अगर उसे नहीं अपनाएंगे तो हम 'ओल्ड फैशन' की उपाधि से अलंकृत हो जाएंगे। लेकिन कई बार वे यह नहीं सोच पाते कि जो भी फैशन चल रहा, उससे मां-बाप और निकटवर्ती लोगों में हमारी छवि कैसी बनेगी। यह भी है कि फैशन के इस दौर में फैशन के साथ चलने के लिए बच्चे ब्रांडेड कंपनी की वस्तुओं की ही ज्यादा पसंद कर रहे हैं। जैसे-जूते यदि ब्रांडेड कंपनी के हों चाहे वह कम पसंद आ रहे हैं और वहीं दूसरे (लोकल ब्रांड) जूते उससे कहीं अच्छे भी हों तो भी जागरूक बच्चे ब्रांडेड कंपनी के जूते ही पहनना पसंद करेंगे। इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता है।

लौट रहे हैं वाइब्रेंट कलर्स

अपने डिफरेंट शेड्स के साथ यह कलर टीनेजर्स से लेकर सेलीब्रिटीज की पहली पसंद बना हुआ है। यह तक कि फैशन डिजाइनर्स ने भी अपने कलेक्शन में इस बार जमकर इस रंग का प्रयोग किया है।

ताजगी भरा अहसास
बीच में कुछ समय गायब रहने के बाद लौटते इस कलर ने

फैशन जगत में एक नई ताजगी भर दी है। इसलिए आप भी अपने बॉर्डरों में छिपे इस वाइब्रेंट कलर को दोबारा देखीकें होकर बाहर निकाल सकती हैं।

खुद करें चयन
यदि आपको ब्राइट यलो पसंद नहीं है, तो आप लाइट और सॉफ्ट येलो कलर्स को चुन सकती हैं। लेमन येलो और

फैशन वर्ल्ड में कलर्स का आना-जाना सामान्य बात है। लेकिन कुछ समय बाद पुराने वाइब्रेंट कलर्स लौटे हैं, जो बहुत ही सुदृढ़ लुक में हैं।

लाइट येलो कलर्स सभी पर फव्वेनें। मिक्स-मेच कई लोगों के लिए सॉलिड येलो पहनना थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसे में आप दूसरे रंगों के कॉम्बिनेशन के साथ इस रंग को पहन सकती हैं। येलो को लाइट ब्लू, बोल्ड ग्रीन, बेबी पिंक और व्हाइट के साथ आराम से मिलाया जा सकता है।

जायका

पालक पनीर



सामग्री

पालक- 500 ग्राम, चीनी आधा छोटी चम्मच, पनीर- 200 ग्राम पनीर को चौकोर टुकड़ों में काट लें, रिफाईड तेल- 2 टेबिल स्पून, हींग- 1-2 पिंच, जीरा-आधा छोटी चम्मच, हल्दी पाउडर- 1/4 छोटी चम्मच, कसूरी मैथी- 2 छोटी चम्मच (डंडियां हटाकर प्रयोग करें), टमाटर- 2-3, हरी मिर्च-3-4, अदरक-1 इंच लम्बा टुकड़ा, बेसन- 2 छोटे चम्मच, क्रीम या मलाई- 2 टेबिल स्पून, लाल मिर्च- 1/4 छोटी चम्मच से कम (यदि चाहें), नमक- स्वादानुसार, गरम मसाला- एक चौथाई छोटी चम्मच, नींबू का रस- 2 छोटी चम्मच

बनाने की विधि

पालक की डंडियां तोड़कर हटा दीजिये, पत्तों को अच्छी तरह धोकर एक बर्तन में डालें, चौथाई कप पानी और चीनी डाल दीजिए, ढंक्कर उबालने रख दीजिए, 5-6 मिनट में पालक उबल जाता है। गैस बन्द कर दीजिये। पनीर के चौकोर टुकड़े काट लीजिए। आप पनीर को तलकर या बिना तले दोनों तरीके से तरी में डाल सकती हैं (पनीर को तलने के लिये नान स्टिक तवा गरम कीजिये, थोड़ा सा तेल डालिये और पनीर के टुकड़े तवे पर डाल कर दोनों ओर हल्का ब्राउन होने तक तल लीजिये) टमाटर को धोइए, टुकड़ों में काटिये। हरी मिर्च के डटल तोड़िये, धोइये। अदरक को छीलिए, धोइए और 3-4 टुकड़े कर लीजिए। इन सबको मिक्सी से बारीक पीस लीजिये। कढ़ाही में तेल डाल कर गरम कीजिये। गरम तेल में हींग और जीरा डाल दीजिए।

जीरा भूनने के बाद, हल्दी पाउडर और कसूरी मैथी डालिए, अब बेसन डालकर थोड़ा सा भूनिए, अब इस मसाले में टमाटर, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट डाल दीजिए और मसाले को 2 मिनट भूनिए, अब क्रीम या मलाई डालिए और मसाले तब तक भूनिए, जब तक मसाले के ऊपर तेल न तैरने लगे। उबले पालक को टंडा होने के बाद मिक्सी से बारीक पीसिए, पालक के पेस्ट को भूने हुए मसाले में मिलाएं। तरी में जितना चाहे गाढ़ी या पतली रखना है, पानी और नमक डाल दीजिए, उबाल के बाद पनीर के टुकड़े डालें, 2-3 मिनट पकाइये। पालक पनीर की सब्जी तैयार है। पालक पनीर की सब्जी में गरम मसाला और नींबू का रस मिला दीजिये।

वेडिंग सीजन में फैशन ट्रेंड

ब्राइडल एशिया एगजीबिशन लगे और शादियों का फैशन फोरकास्ट न किया जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? इस एगजीबिशन से निकले कौन से ट्रेंड इस बार शादियों में आपको दिखाई देने वाले हैं। जिससे चार चांद लग जाए।

का बायस बना था तो कहीं मजेंटा पिंक के रूप में तड़कता-भड़कता ग्लैमर नजरों को लुभा रहा था। न सिर्फ परिधान बल्कि ज्वेलरी, एसेसरी और फुटवियर तक में पिंक रंग चमकेगा। फैशन डिजाइनर जया राठौड़ की मानें तो शादी के परिधानों के लिए पिंक लहंगे या साड़ी को सुनहरे तारों से बुना जाएगा, जिससे पिंक में गोल्ड इफेक्ट आए या फिर इसके साथ मोव रंग की जुगलबंदी की जाएगी, ताकि रॉयल अहसास महसूस हो। ज्वेलरी को भी पिंक स्टोन से हाइलाइट किया जाएगा। घेर वाले परिधान: ब्राइडल एशिया में डिजाइनरों ने जिस चीज पर सबसे ज्यादा फोकस किया, वह थी वेस्टलाइन। यानी कमर पर से फिट ड्रेस। ब्राइडल गाउन हों या अनारकली कुर्तियां या फिर लहंगे। हर परिधान की खासियत है कि उसे कमर से फिट रखा जाता है। उसके बाद टेयर सारा घेर देते हुए खुला छोड़ दिया गया था। ये सारे परिधान फेमिनिटी को उभारने की पूरी कोशिश कर रहे थे।

फैशन डिजाइनरों के मुताबिक, इस बार शादियों में इंडोवेस्टर्न का जलवा दिखेगा। डिजाइनर भारतीय फैब्रिक से भारतीय परिधान बनाएंगे। उन पर कढ़ाई भी भारतीय रहेगी, मगर उसे शैप और कट से वेस्टर्न लुक दिया जाएगा। वेस्टलाइन को हाइलाइट करने के लिए जहां लेस, जरी और स्टोन का इस्तेमाल किया जाएगा, वहीं घेरे की खूबसूरती बढ़ाने के लिए फ्रिल, नेट और जरी का इस्तेमाल किया जाएगा। चोली कट और जैकेट : इस वेडिंग सीजन में अपर वियर यानी लहंगे के ऊपर पहनने वाले परिधानों में खूब वैरायटी दिखाई देगी। अगर आप ग्लैमरस लुक चाहती हैं तो आपके लिये बेकलेस शॉर्ट चोली बेहतर रहेगी। अगर आप एलिगेंस लुक चाहती हैं तो नेहरू कॉलर कमर तक की या घुटने वाली लेंथ वाली जैकेट ट्राई कर सकती हैं। इस बाबद जया बताती हैं चोली तो पहले से चलन में है, मगर जैकेट ने इस बार वापसी की है।



घर की खिड़कियों को खूबसूरत बनाएं



घर की खिड़कियों की आपके कमरे के लुक और फील को बढ़ाने में अहम भूमिका होती है। जाहिर-सी बात है कि दीवारों को उचित रंग देने के बाद खिड़कियों को सजाने के बारे में आप सोचेंगी। अपने कमरे की खिड़कियों को खूबसूरत और कूल बनाना चाहती हैं, तो परदे के रंग, रॉड और फैब्रिक की खूबसूरती पर जरूर गौर फरमाएं।

रंग-बिरंगे रेशमी परदे
परदे का रंग आपके कमरे के डेकोर से मेल खाता होना चाहिए। अतः कमरे के लिए परदे का चयन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें। साधारण से कमरे में हल्के रंगों के परदे और बड़े कमरे के लिए हेवी लुक वाले स्ट्राइलिश परदे परफेक्ट हैं। कमरे में खिड़की की सजावट का एक बहुत आसान तरीका परदे में रिबन या गाँठ बांधना भी है। आप इसे घर में भी बना सकती हैं।



प्रिंटेड और प्लेन परदे
प्रिंटेड और प्लेन परदे को मिलाकर खिड़कियों पर लगाएँ। इससे अच्छा लुक आएगा। सार्टन की कोई पुरानी साड़ी हो, तो आप लेस लगाकर परदा तैयार कर सकती हैं या फिर कुशन कवर भी बना सकती हैं। सोफा व कुशन कवर का चयन भी परदे के रंग से मैच करता हुआ ही खरीदें। इन दिनों हरे रंग का कॉम्बिनेशन ज्यादा डिमांड में हैं।

लाइट व डार्क परदे
ऑफिस हो या घर आप अपने मनपसंद के अनुसार परदे खरीद सकते हैं। ऑफिस में लाइट कलर के व घरों में डार्क कलर के परदे सुंदर व आकर्षक लगते हैं। दोनों में ही कलर व डिजाइन एक से बढ़कर एक आ रहे हैं। इसमें 50 रुपये से 300 रुपये प्रतिमीटर की रेंज उपलब्ध है।

परदे को रॉयल लुक दे कर्टन रॉड

कर्टन रॉड का इस्तेमाल परदों को हेंग करने के लिए किया जाता है। घर में यदि डिजाइनर कर्टन रॉड लगे हों, तो कमरों की खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। आजकल कर्टन रॉड की कई रेंज मार्केट में उपलब्ध हैं। इनमें रंगों की वैरायटी में देखने को मिल जाएगी, फिर भी सफेद, डार्क ब्राउन और ब्लैक रंग की ज्यादा डिमांड है। ये लकड़ी, एल्युमिनियम, आयरन, फाइबर के अलावा प्लास्टिक में भी उपलब्ध हैं। इन दिनों स्टील और मेटैलिक सर्फेस के लिए मेमेटिक कर्टन रॉड में मिल रहे हैं। ऐसे रॉड को दीवारों से लगाने के लिए ड्रिलिंग की जरूरत नहीं पड़ती। परदे के हिसाब से रॉड का चुनाव करें, ताकि परदे का वजन रॉड आसानी से उठा सके। यदि हेवी परदे लगाने हों, तो रॉड का मेटैरियल भी उसी के हिसाब से खरीदें।

रायपुर, बुधवार 04 दिसंबर 2024

पीएम मोदी ने बाढ़ के हालात पर सीएम स्टालिन से की बात

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से बात की और चक्रवात फेगल और भारी बारिश के कारण आई भीषण बाढ़ के मंदेनजर राज्य को पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। फोन के माध्यम से बातचीत में, मोदी ने तमिलनाडु, विशेषकर विलुपुम में नुकसान की सीमा के बारे में जानकारी ली, जहां अभूतपूर्व बाढ़ ने बड़े पैमाने पर व्यवधान पैदा किया है। स्टालिन ने प्रधानमंत्री को बताया कि राज्य सरकार आपदा से प्रभावी ढंग से निपट रही है और प्रभावित लोगों को राहत प्रदान कर रही है। उन्होंने विन्तीय सहायता के लिए अपना अनुरोध दोहराया और केंद्र सरकार से विस्तृत क्षति आकलन के लिए एक टीम भेजने का आग्रह किया। एक्स पर एक पोस्ट में एमके स्टालिन ने लिखा कि उन्होंने मोदी से आग्रह किया कि वे इस तूफान के कारण तमिलनाडु के लोगों को राहत प्रदान करें और तूफान से हुए नुकसान का विस्तृत आकलन करने के लिए एक केंद्रीय समिति भेजें।

आज हिंसा प्रभावित संभल का दौरा कर सकते हैं राहुल गांधी

नई दिल्ली। विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बुधवार को हिंसा प्रभावित संभल का दौरा करने की उम्मीद है। सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है। 24 नवंबर को दूसरे सर्वेक्षण के दौरान हिंसा भड़क उठी जब प्रदर्शनकारी शाही जामा मस्जिद के पास एकत्र हुए और सुरक्षा कर्मियों से भिड़ गए। इसके बाद हुई हिंसा में चार लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। इससे पहले उत्तर प्रदेश इकाई के प्रमुख अजय राय के नेतृत्व में कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल को संभल जाने से रोक दिया गया। भारी ड्रामे के बीच, राय, जो अपनी कार में ड्राइवर की सीट पर बैठे थे और उनके बगल में पार्टी के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया थे, वे तथ्य-खोज दौरे के लिए नहीं निकल सके, यहां तक कि पुलिस और नारे लगा रहे पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई। पुलिस ने रविवार रात को राज्य की राजधानी में पार्टी के कार्यालय और उसके कई नेताओं के आवासों के बाहर बैरिकेड्स लगा दिए थे।

केजरीवाल ने कानून व्यवस्था को लेकर केंद्र पर साधा निशाना

नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को मंगोलपुरी हत्याकांड पर प्रतिक्रिया दी और दिल्लीवासियों से एकजुट होकर अपराध के खिलाफ आवाज उठाने का आग्रह किया। एक्स पर एक पोस्ट में केजरीवाल ने कहा कि सोमवार रात मंगोलपुरी में एक व्यक्ति की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। रविवार को दिल्ली में तीन हत्याएं हुई। पूर्व सीएम ने दिल्ली के नागरिकों से आग्रह करते हुए कहा कि सभी दिल्लीवासियों को एक साथ आना चाहिए और अपराध के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह बयान बाहरी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में सोमवार रात मामूली बात पर हुए विवाद के बाद 19 वर्षीय एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या किए जाने के बाद आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आज पूरी दिल्ली में दहशत है लेकिन अमित शाह और उनकी दिल्ली पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रहे।

महाराष्ट्र में सीएम के नाम पर मुहर नहीं लगने पर विपक्ष ने ली चुटकी

मुंबई। चर्चा है कि महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन पांच दिनों के भीतर होना है, लेकिन सीएम के नाम का ही अता-पता नहीं है। वहीं, विपक्ष लगातार इस को लेकर कटाक्ष कर रहा है। उसका कहना है कि महाराष्ट्र में चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है। महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम पर शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने कहा, एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं। एक मुख्यमंत्री कैसे गायब हो सकता है? महाराष्ट्र में खेल चल रहा है। 10 दिन हो चुके हैं। उनके (महायुति) पास भारी बहुमत है लेकिन उसके बाद भी वे लोग मुख्यमंत्री का नाम अब तक घोषित नहीं कर पा रहे हैं। यह सब दिल्ली का खेल है। महाराष्ट्र में जो मरकट लीला चल रही है वो दिल्ली से चलाई जा रही है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, हम एक बात समझ सकते हैं— अगर सरकार पूर्ण बहुमत के साथ नहीं होती है, तो संख्या लानी होगी। लेकिन यहां उन्होंने दो तिहाई से अधिक बहुमत दर्ज किया। फिर वे किस पर काम कर रहे हैं?

संसद में प्रियंका को चौथी पंक्ति में 517 नंबर की सीट मिली

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में पहली सीट पर बैठेंगे, वहीं विपक्ष की ओर उनके ठीक सामने दूसरे और से पहली सीट पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बैठेंगे। लोकसभा सचिवालय से जारी सौटिंग प्लान में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को अब गृहमंत्री अमित शाह के बगल में पहली पंक्ति में चौथी सीट दी गई है। इससे पहले वह दूसरे कॉलम में सीट नंबर 58 पर बैठते थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री के बगल में दूसरी सीट पर बैठेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को अगली पंक्ति में सीट नंबर 355 आवंटित हुई है। तृणमूल कांग्रेस नेता सुदीप बंदोपाध्याय यादव के बगल में बैठेंगे। वायनाड से जीतकर पहली बार लोकसभा पहुंची कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड़ा को चौथी पंक्ति में सीट नंबर 517 मिली है। सदन में पश्चिम बंगाल से बशरहाट के सांसद टीएमपी के एस के नूरुल इस्लाम के निधन के बाद से एक सीट खाली है।

अदाणी मुद्दे पर इंडिया गठबंधन में दो फाड़, कांग्रेस के प्रदर्शन से सपा-टीएमसी ने बनाई दूरी

नई दिल्ली। संसद के शीतकालीन सत्र के सातवें दिन मंगलवार को भी हंगामा जारी रहा। दरअसल, अदाणी मामले पर विपक्ष ने लोकसभा से वॉकआउट किया। उसके बाद संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन करने लगे। विपक्षी दलों के सांसदों के हाथ में मोदी-अदाणी एक हैं और भारत अदाणी के खिलाफ जवाबदेही की मांग करता है, लिखी तख्तियां दिख रही थीं। इस प्रदर्शन में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, सांसद प्रियंका गांधी शामिल हुए। हालांकि, इससे समाजवादी पार्टी (एसपी) और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने दूरी बना ली है। ऐसे में सरकार के खिलाफ विपक्ष बिखरता नजर आया। इस दूरी ने एक बार फिर इंडिया गठबंधन में आई दरार को सामने ला दिया।

सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध कर रहे : राशि थरूर

कांग्रेस सांसद राशि थरूर ने कहा कि हम मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। हम सदन के अंदर प्रदर्शन नहीं कर सकते इसलिए हमने संसद परिसर में विरोध किया है। टीएमसी के न शामिल होने पर कहा उन्होंने, हमारे बीच अबतक और मामलों में सही समन्वय चल रहा है। उनको पता है बंगाल में हम लोग एक साथ नहीं हैं। इसलिए शायद वह इस विषय पर भी अलग हैं। संसद में किस विषय पर बात होगी यह सरकार तय करेगी। मगर विपक्ष और कोई रास्ता निकाल लेगा अपने विषयों पर बात करने का।

विपक्षी पार्टियों में क्यों है मतभेद?

25 नवंबर से शुरू हुए संसद के शीतकालीन सत्र में लगातार गतिरोध बना हुआ है। कांग्रेस पार्टी का पूरा फोकस अदाणी मामले को लेकर है, लेकिन समाजवादी पार्टी संभल हिंसा पर चर्चा की मांग कर रही है। इससे पहले सोमवार को संसद की कार्यवाही से पहले इंडिया ब्लाॉक के नेताओं की मुलाकात राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे से हुई थी, जिसमें राहुल गांधी तो शामिल हुए थे, लेकिन टीएमसी का कोई सांसद नहीं पहुंचा था।

दरअसल तृणमूल कांग्रेस चाहती है कि सदन में महंगाई, बेरोजगारी, किसान, उर्वरक, विपक्षी राज्यों



को मिलने वाले पैसे में कटौती और मणिपुर जैसे मुद्दों को लेकर चर्चा हो। वहीं कांग्रेस चाहती है कि अदाणी मुद्दे पर ही चर्चा हो। कांग्रेस के रूख से सपा भी किनारा करती दिख रही है। वहीं अन्य विपक्षी दल भी चाहते हैं कि किसान, संभल और मणिपुर जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हो। यानि विपक्षी दलों में टीएमसी का रुख साफ है कि संसद में सभी मुद्दों पर चर्चा हो, कमोबेश ऐसा ही कुछ समाजवादी पार्टी भी चाहती है।

सपा का क्या कहना है?

सपा सांसदों ने मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की और संभल मुद्दे पर चर्चा का अनुरोध किया। सपा नेताओं के अनुसार अदाणी का मुद्दा संभल जितना बड़ा नहीं है। सपा सांसद धर्मेश यादव ने कहा कि हमारे लिए अदाणी से बड़ा मुद्दा किसान हैं। यानि कांग्रेस महोदय ही अदाणी की रट लगाए बैठे हो, मगर विपक्ष के कई दल और भी मुद्दों पर बहस करना चाहते हैं। सपा की सांसद इकरा हसन ने कहा, अदाणी मुद्दे पर चर्चा महत्वपूर्ण है। हालांकि, चूंकि पांच लोगों की मौत हो गई है, इसलिए संभल समाजवादी पार्टी के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता वाला मुद्दा बन गया है।

रेणुका चौधरी के बयान पर भी बवाल

इस बीच कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी के एक

बयान पर विवाद हो गया है। चौधरी ने कहा, हमारी तरफ से कोशिश है कि सदन की कार्यवाही सुचारु ढंग से चले क्योंकि जनता ने हमें चुनकर संसद भेजा है और वे चाहते हैं कि हम उनकी आवाज को यहां बुलंद करें। अगर सरकार सदन चलाना चाह रही है तो चलेगा, अगर वह नहीं चलाना चाह रही है तो नहीं चलेगा। सब समझते हैं कि ये पड़यंत्र क्या है। चौधरी ने कहा कि सदन चलाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है बल्कि कुर्सी पर बैठे लोगों की जिम्मेदारी है। अगर वे लायक हैं तो चलाएंगे, नालायक हैं तो नहीं चलाएंगे।

कांग्रेस सांसद ने यह दी सफाई

अदाणी मामले चल रहे विरोध में टीएमसी के शामिल ना होने पर कांग्रेस राज्यसभा सांसद नासिर हुसैन ने कहा, जो मुद्दे हम सबने तय किए थे उन पर

अदाणी मामले पर संसद में इंडिया गठबंधन के विरोध में टीएमसी के शामिल नहीं होने पर भाजपा सांसद समिक भट्टाचार्य ने कहा, आप गठबंधन की स्थिति देख सकते हैं। कभी टीएमसी गायब है तो कभी आम आदमी पार्टी गायब है। कांग्रेस जहां भी लोगों के पास जाती है, जनता उन्हें वहां ठुकरा देती है। कांग्रेस के पास अब सिर्फ एक जगह है— संसद का गेट या फिर सदन नहीं चलने देना। यही कांग्रेस का एजेंडा है। कोई नहीं जानता कि टीएमसी कब और कहा जाएगी। ममता बनर्जी चाहती थीं कि मल्लिकार्जुन खरगे इस गठबंधन का चेहरा बनें। उन्होंने उधें देश का पीएम बनने का प्रस्ताव दिया था। वही मल्लिकार्जुन खरगे के स्पष्ट आह्वान में अब टीएमसी शामिल नहीं है। अब यह सब नाटक है। वे लोकतंत्र की मर्यादा को नुकसान पहुंचा रहे हैं।

हम चाहते हैं कि बात हो। इसके लिए हम आने वाले समय में और बात करेंगे। हम चाहते हैं सदन चले और बात हो। बांग्लादेश के मुद्दे पर भी बात होनी चाहिए। वहां अल्पसंख्यकों को सुरक्षा मिलनी चाहिए।

विपक्ष के प्रदर्शन पर भाजपा ने साधा निशाना

अदाणी मामले पर संसद में इंडिया गठबंधन के विरोध में टीएमसी के शामिल नहीं होने पर भाजपा सांसद समिक भट्टाचार्य ने कहा, आप गठबंधन की स्थिति देख सकते हैं। कभी टीएमसी गायब है तो कभी आम आदमी पार्टी गायब है। कांग्रेस जहां भी लोगों के पास जाती है, जनता उन्हें वहां ठुकरा देती है। कांग्रेस के पास अब सिर्फ एक जगह है— संसद का गेट या फिर सदन नहीं चलने देना। यही कांग्रेस का एजेंडा है। कोई नहीं जानता कि टीएमसी कब और कहा जाएगी। ममता बनर्जी चाहती थीं कि मल्लिकार्जुन खरगे इस गठबंधन का चेहरा बनें। उन्होंने उधें देश का पीएम बनने का प्रस्ताव दिया था। वही मल्लिकार्जुन खरगे के स्पष्ट आह्वान में अब टीएमसी शामिल नहीं है। अब यह सब नाटक है। वे लोकतंत्र की मर्यादा को नुकसान पहुंचा रहे हैं।

मनरेगा को लेकर शिवराज सिंह चौहान और कल्याण बनर्जी भिड़ें

नई दिल्ली। अदाणी समूह पर लगे आरोपों और संभल हिंसा समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर संसद के शीतकालीन सत्र का पहला हफ्ता हंगामे की भेंट चढ़ चुका है। हालांकि, मंगलवार को सातवें दिन कार्यवाही हुई। इस दौरान, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी' (मनरेगा) योजना के तहत बजट आवंटन का दुरुपयोग किया गया तथा 'अपात्र' लोगों को लाभ पहुंचाने का अपराध किया गया है। मनरेगा पर एक सवाल के दौरान पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर से सांसद कल्याण बनर्जी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भिड़ गए। दरअसल कल्याण बनर्जी ने अपने सवाल में आरोप लगाया कि 2022-23 में बंगाल को केंद्र की तरफ से कोई पैसा नहीं मिला। बनर्जी ने कहा कि केंद्र दलील दे रही है कि इस योजना में गैरकानूनी काम हुए हैं, क्या गैरकानूनी काम हुए हैं? बनर्जी के सवाल का जवाब देने के लिए उठे शिवराज चौहान ने कहा कि मनरेगा की राशि निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए होती है। अगर वे राशि निश्चित उद्देश्य की पूर्ति में नहीं जा सकती है तो इसे रोका जा सकता है। मंत्री ने आरोप लगाया कि कुछ निश्चित लोगों को लाभ पहुंचाने का अपराध पश्चिम बंगाल में किया गया। उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल सरकार ने बड़े कामों को छोटा करके कुछ खास लोगों को लाभ पहुंचाने का अपराध किया है। इस योजना के तहत अपात्र लोगों को पात्र बनाया गया और पात्र लोगों को अपात्र बनाया गया, यह साबित हो चुका है। ग्रामीण विकास योजनाओं के नाम बदले गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम बदलकर अपना नाम रखने का अपराध किया है। इसी योजना के तहत भी अपात्र लोगों को लाभ दिया गया और पात्र लोगों को छोड़ दिया गया। यह राशि दुरुपयोग के लिए नहीं है, यह अपात्र लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं है। पश्चिम बंगाल सरकार ने इस पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की। जैसा कि पीएम मोदी ने कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन हम राशि का दुरुपयोग नहीं होने देंगे। मोदी जी कहते हैं कि न खाऊंगा, न खाने दूंगा। उनके जवाब के दौरान तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने टोकाटोकी की। मनरेगा से जुड़े कुछ पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए ग्रामीण विकास राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी ने कहा कि धन के आवंटन की कमी की बात गलत है तथा मांदेश्य कम होने की बात भी गलत है क्योंकि इसका निर्धारण महंगाई से जुड़ा है।

स्टील प्रमुख समाचार

यशस्वी जायसवाल के साथ कौन करेगा ओपन?

एडिलेड। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 6 दिसंबर से दूसरा टेस्ट मैच एडिलेड में डे-नाइट का खेला जाएगा। वहीं कप्तान रोहित शर्मा ने भी टीम इंडिया को ज्वाइन कर लिया है। हालांकि, उनका बल्ले अभी भी खामोश है लेकिन वे कप्तान हैं तो उनका खेलना तय है। ऐसे में संकेत ये है कि पिंक बॉल टेस्ट मैच में एडिलेड के मैदान पर यशस्वी जायसवाल के साथ ओपन कौन करेगा? मौजूदा समय में केएल राहुल का नाम सबसे ऊपर है, क्योंकि उन्होंने पर्थ में अच्छी बल्लेबाजी की थी और प्रैक्टिस मैच में भी उन्होंने रन बनाए थे। साथ ही विदेश धरती पर केएल राहुल के बतौर ओपनर पिछले आंकड़े भी अच्छे रहे रहे हैं।

बता दें कि, साल 2015 के बाद से केएल राहुल एकमात्र बल्लेबाज इंटरनेशनल क्रिकेट में हैं, जिन्होंने घर से बाहर ओपनर के तौर पर 6 शतक जड़े हैं। दूसरे नंबर पर इस लिस्ट में उस्मान ख्वाजा हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए विदेशी सरजमां पर पिछले 10 साल में 5 ही शतक जड़े हैं। इसके अलावा 4-4 शतक इस समय सीमा में अन्य सात क्रिकेटर्स ने जड़े हैं, जिनमें पाकिस्तान के अजहर अली, वेस्टइंडीज के जैम ब्रेथवेट, भारत के शिखर धवन, साउथ अफ्रीका के डीन एग्गर, श्रीलंका के दिमथ करुणारत्ने और न्यूजीलैंड के टॉम लैतम का नाम है। हालांकि, इनमें से कई रिटायर हो चुके हैं लेकिन केएल राहुल के आंकड़े बेहतरीन हैं। केएल राहुल ने टेस्ट करियर में 8 शतक हैं और इनमें से 6 शतक वे ओपनर के तौर पर विदेशी सरजमां पर जड़ चुके हैं। इन आंकड़ों को देखकर रोहित शर्मा खुद ही कुर्बानी दे सकते हैं और वे फिर से मिडिल ऑर्डर में खेलते हुए दिख सकते हैं। वहीं अब सवाल ये है कि क्या मैनेजमेंट ये रिस्क लेगा कि रोहित शर्मा को 5 या 6 करपा जाए या केएल राहुल को कहा जाएगा कि आप नंबर 5 या 6 पर आओ, क्योंकि वे पिछले कुछ मैच उसी नंबर पर खेल रहे हैं।

आर्थिक/वणिज्य/वित्त प्रमुख समाचार

शेयर बाजार में तीसरे दिन भी तेजी, संसेक्स 598 अंक बढ़ा

नई दिल्ली। ग्लोबल मार्केट से मिले मजबूत रुझानों और बैंकिंग, मेटल तथा तेल कंपनियों के शेयरों में तेजी के बीच मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार में लगातार तीसरे सत्र में शानदार तेजी देखी गई। 30 शेयरों वाला, बीएसई संसेक्स 597.67 अंक या 0.74 प्रतिशत की शानदार बढ़त लेकर 80,845.758 पर बंद हुआ। संसेक्स में आज 80,244.78 और 80,949.10 के रेंज में कारोबार हुआ। वहीं, दूसरी तरफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 181.10 अंक या 0.75 प्रतिशत मजबूत होकर 24,457.15 पर बंद हुआ। निफ्टी में आज 24,280.00 और 24,481.35 के रेंज में कारोबार हुआ। संसेक्स के 30 शेयरों में से 25 शेयर हरे निशान पर बंद हुए। अदाणी पोर्ट्स, एनटीपीसी, एक्सिस बैंक, एसबीआई और एलएंडटी संसेक्स के टॉप-5 गेनर्स रहे।

टाटा पावर रिन्यूएबल्स एनर्जी ने सोलर प्रोजेक्ट किया शुरू

नई दिल्ली। टाटा पावर की इकाई टाटा पावर रिन्यूएबल्स एनर्जी ने मध्य प्रदेश के नीमच में 431 मेगावाट डीसी सौर परियोजना चालू करने की मंगलवार की घोषणा की। टाटा पावर ने बयान में कहा, 1,635.63 एकड़ में फैली इस परियोजना में सिंगल-एक्सिस ट्रैकर्स और बाई-फेजियल मांड्यूल का अनूठा संयोजन है। इससे भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए एक नया मानक स्थापित होगा। इसमें कोटा गया, इस अभिनव एकीकरण ने पूरी प्रणाली की दक्षता को 15 प्रतिशत से अधिक बढ़ा दिया है, जिससे विस्तारित घंटों के लिए अधिकतम बिजली आपूर्ति संभव हो गई है। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक दीपेश नंदा ने कहा, "हमें नीमच में 431 मेगावाट डीसी सौर परियोजना के सफल संचालन की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है।"

निसस फाइनेंस सरविजेस का आईपीओ आज खुलेगा

नई दिल्ली। निसस फाइनेंस सर्विसेस का आईपीओ बोली लगाने के लिए बुधवार यानी 4 दिसंबर को खुलेगा। कंपनी ने इश्यू प्राइस के अपर एन्ड पर 114.24 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बनाई है। कंपनी की तरफ से दाखिल दस्तावेजों के अनुसार, इश्यू के तहत 5,645,600 शेयर ऑफर फॉर सेल के लिए रखे गए हैं। इसमें प्रोमोटर अमित अनील गोयनका के 700,800 शेयर भी शामिल हैं, जिनकी प्रति शेयर फेस वैल्यू 10 रुपये है। कंपनी ने अपने आईपीओ का प्राइस बैंड 170-180 रुपये प्रति शेयर रखा है। एक लॉट में 800 शेयर शामिल हैं। रिटेल निवेशक मिनिमम 800 शेयर या इसके मल्टिपल में बोली लगा सकते हैं। इस हिसाब से एक लॉट का भाव 144,000 रुपये बनता है। कंपनी के अनलिस्टेड शेयर बोली लगाने के लिए खुलने से पहले ही ग्रे मार्केट में दाहड़ मार रहे हैं। निसस फाइनेंस सर्विसेस आईपीओ का जीएमपी 3 दिसंबर को 230 रुपये चल रहा था।

आरबीआई ने बैंकों से निष्क्रिय खातों में कमी लाने को कहा

नयी दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों से कहा कि वे आवश्यक कदम उठाकर निष्क्रिय या 'फ्रीज' किए गए खातों की संख्या को 'तत्काल' कम करें और तिमाही आधार पर इनकी संख्या के बारे में भी जानकारी दें। ऐसे खातों में पड़ी धनराशि की बढ़ती मात्रा पर चिंता व्यक्त करते हुए आरबीआई ने कहा कि उसके पर्यवेक्षी निरीक्षणों से कई समस्याओं का पता चल रहा है, जिसके कारण खाते निष्क्रिय हो रहे हैं या 'फ्रीज' हो रहे हैं। आरबीआई के पर्यवेक्षण विभाग के विश्लेषण से पता चला कि कई बैंकों में निष्क्रिय खातों/बिना दावा किए गए जमा की संख्या उनकी कुल जमा राशि के साथ-साथ निरपेक्ष रूप से भी अधिक थी। सभी बैंकों के प्रमुखों को जारी अधिसूचना में कहा गया, बैंकों को निष्क्रिय/जमा किए गए खातों की संख्या में कमी लानी के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी जाती है।

भारतीय आर्थिक दर्शन एवं प्राचीन भारत में आर्थिक विकास

(गतांक से आगे...)
प्रह्लाद सबनानी
हां, भारत के प्राचीन शास्त्रों में यह जरूर कहा गया है कि अर्थ और काम को बेलगाम नहीं छोड़ना चाहिए। अर्थ और काम को मर्यादा में ही रहना चाहिए। धन अर्जित करने पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है परंतु यह धर्म का पालन करते हुए कामना चाहिए। अर्थात्, अर्थ को धर्म के साथ जोड़ा दिया गया है। इसी प्रकार काम को भी धर्म के साथ जोड़ा गया है। उपभोग यदि धर्म सम्मत और मर्यादित होगा तो इस धरा का दोहन भी सीमा के अंदर ही रहेगा। अतः कुल मिलाकर अर्थशास्त्र में भी नैतिकता का पालन होना चाहिए। प्राचीन भारतीय अर्थशास्त्र एवं वर्तमान अर्थशास्त्र में यह ही एक बहुत बड़ा अंतर है। आजकल कहा जाता है कि नैतिकता अर्थशास्त्र से कोई लेना देना नहीं है। जबकि

वस्तुतः ऐसी कोई भी अर्थव्यवस्था, अर्थतंत्र और विकास का कोई भी तंत्र जिसमें नैतिकता को स्वीकार न किया जाय वह चल नहीं सकती और वह समाज का भला नहीं कर सकती। अर्थ को प्रदान किए गए महत्व के चलते ही प्राचीनकाल में भारत में दूध की नदियां बहती थीं, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, भारत का आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पूरे विश्व में बोलबाला था। भारत के ग्रामीण इलाकों में निवास कर रहे नागरिक बहुत सम्पन्न हुआ करते थे। कृषि उत्पादकता की दृष्टि से भी भारत का पूरे विश्व में डंका बजता था तथा खाद्य सामग्री एवं कपड़े आदि उत्पादों का निर्यात भारत से पूरे विश्व को होता था। भारत के नागरिकों में देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी रहती थी तथा उस खंडकाल में भारत का वैभव काल चल रहा था, जिसके

विकास में आपकी भूमिका को आंकने के पश्चात किया जाता है। भव्यता दिखावा है, भव्यता प्रदर्शन है, अतः केवल भव्यता के कारण किसी का जीवन ऊंचाईयों को नहीं छू सकता है, इसके लिए दिव्यता होनी चाहिए, अर्थात् समाज की भलाई के लिए अधिक से अधिक कार्य करना होता है। अर्थ को धर्म से जोड़ने के साथ ही, प्रकृति के संरक्षण की बात भी भारतीय पुराणों में मुखर रूप से कही गई है। भारतीय सनातन हिंदू संस्कृति के अनुसार नदियाँ, पहाड़ों, जंगलों, जीव जंतुओं में भी देवताओं का वास है, ऐसा माना जाता है। इसीलिए यह कहा गया है कि इस पृथ्वी पर उपलब्ध संसाधनों का दोहन करें, शोषण नहीं करें। सर जगदीश चंद्र बसु ने एक परीक्षण किया और इस परीक्षण के माध्यम से यह सिद्ध किया कि पेड़ पौधों में भी वैसी ही संवेदना होती है जैसी मनुष्यों में संवेदना होती है। जिस प्रकार मनुष्य रोता है, हंसता है,

प्रसन्न होता है, नाराज होता है, इसी प्रकार की संवेदनाएं पेड़ पौधों में भी पाई जाती हैं। सर जगदीश चंद्र बसु ने वैज्ञानिक तरीके से जब यह सिद्ध किया तो दुनिया में तटलका मच गया। जबकि भारतीय शास्त्रों में तो इन बातों का वर्णन सदियों पूर्व ही मिलता है। जब इन तथ्यों को वैज्ञानिक आधार दिया गया तो अब पूरी दुनिया भारत के इन प्राचीन विचारों पर साथ खड़ी नजर आती है। भारतीय मनीषियों ने इसीलिए यह बार बार कहा है कि पेड़ पौधों की रक्षा करें, इन्हें काटें नहीं। क्योंकि, इससे पर्यावरण की रक्षा तो होती ही है, साथ ही, पेड़, पौधों के रूप में एक प्रकार से किसी प्राणी की हत्या करने से भी बचा जा सकता है। भारतीय संस्कृति में यह भावना रही है कि व्यक्ति का सम्पूर्ण विकास हो एवं उसे पूर्ण सुख की प्राप्ति हो। इसलिए, उक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ही देश में सामाजिक एवं आर्थिक रचना होनी चाहिए।



फिर शुरू होगी 5वीं-8वीं बोर्ड परीक्षा, स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश



रायपुर। कैबिनेट के फैसले के बाद कक्षा 5वीं और 8वीं की केंद्रीकृत परीक्षा लेने के लिए मंगलवार को स्कूल शिक्षा विभाग ने दिशा निर्देश जारी किया है। इसके तहत राज्य के सभी कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किया गया है। उल्लेखनीय है कि, वर्ष 2010-11 में 5 वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा को समाप्त किया गया था। जिसके तहत प्रत्येक बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। जिसके वजह से किसी बच्चों को फेल नहीं किया जाता था। बोर्ड परीक्षा बंद करने से विद्यार्थियों को शैक्षणिक गुणवत्ता पर असर को देखते हुए एक बार फिर से केंद्रीकृत परीक्षा लेने का फैसला लिया गया है। जिसके तहत प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में कक्षा 5 वीं और 8वीं को नियमित परीक्षा ली जाएगी।

विकसित राष्ट्र बनाने में दिव्यांगजन निभा रहे अहम भूमिका: राजवाड़े

अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले दिव्यांगजन और संस्थाएं राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित



रायपुर। समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा विकसित राष्ट्र बनाने में दिव्यांगजन अहम भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य में दिव्यांगजनों के सर्वाधिकरण पुनर्वास एवं उनके हित के संरक्षण के लिए अनेक कार्य किए जा रहे हैं। वे आज राजधानी रायपुर के साईंस कॉलेज

में मैदान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस समारोह को सम्बोधित कर रही थीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंककाम वर्मा ने की। इस मौके पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले दिव्यांगजन और संस्थाओं को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। समाज कल्याण मंत्री राजवाड़े ने आगे कहा कि राज्य में दिव्यांग जनों के

कल्याणार्थ एवं पुनर्वास हेतु विभिन्न योजनाएं तथा कार्यक्रम संचालित हैं। जिसमें से सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत पेंशन योजनाएं कृत्रिम अंग सहायक उपकरण प्रदाय, मोटराइज्ड ट्राईसाईकिल वितरण, छात्रवृत्ति सहित अन्य योजना का लाभ सभी दिव्यांगजनों को मिल रहा है। प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों के कल्याण तथा हित में बेहतर कार्य कर रही है हम आगे भी आपके हितों के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंककाम वर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि दिव्यांग जनों को समाज के लोगों का भरपूर प्यार और प्रोत्साहन मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन आज देश और प्रदेश में विभिन्न कौशलान स्थानों पर दिव्यांगजन संघ को दिव्यांगजन राज्य

माधवराव सप्रे उत्ततर माध्यमिक शाला पीएमश्री योजना में होगा शामिल - बृजमोहन अग्रवाल

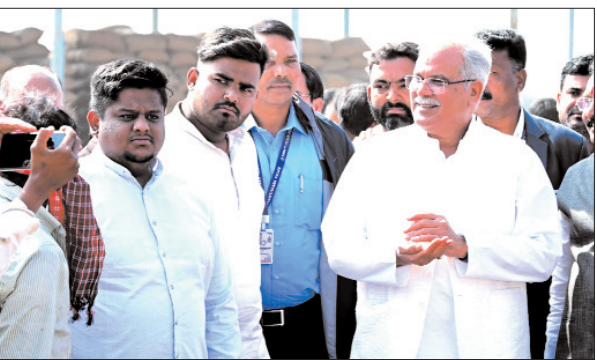
रायपुर। शहर की प्राचीनतम स्कूल माधवराव सप्रे उत्ततर माध्यमिक शाला को पीएमश्री योजना में शामिल कराए जाने की घोषणा रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने की, ताकि यहां के बच्चों को भी गुणवत्तापूरक उच्च शिक्षा मिल सके। अगले सत्र से कॉमर्स आर्ट्स साईंस मैथ्स सहित सभी संकाय की सुविधा यहां होगी। इसके लिए सभी आवश्यक प्रक्रिया पूरा करने के निर्देश उन्होंने शाला परिसर में ही जिला शिक्षा अधिकारी श्री खंडेलवाल को दिए। स्मार्ट कंप्यूटर रूम के उद्घाटन अवसर पर उन्होंने यह भी कहा कि जल्द ही यहां स्मार्ट लाइब्रेरी भी बनेगी।



इस स्कूल की अपनी अलग ही पहचान है। यहां से पढ़कर निकले छात्रों ने अलग-अलग क्षेत्रों में नाम रोशन किया है। सन एंड सन रूप के सहयोग से तैयार स्मार्ट कंप्यूटर रूम के लिए धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा व सामाजिक सरोकार से जुड़े कई उल्लेखनीय कार्य इनके द्वारा किए गए हैं। स्मार्ट कंप्यूटर रूम तो बन गया है अब जल्द ही यहां स्मार्ट लाइब्रेरी भी बनाया जायेगा। नव निर्वाचित विधायक सुनील सोनी ने भी शाला के विकास में हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। शाला विकास समिति की ओर से सांसद बृजमोहन अग्रवाल

प्रदेश के सभी धान खरीदी केंद्रों में गए कांग्रेस के नेता

रायपुर। धान खरीदी में किसानों की समस्याओं देखने तथा उस समस्याओं के निराकरण के लिये सरकार का ध्यानकर्षण करने के लिये कांग्रेस ने प्रदेश की सभी धान खरीदी केंद्रों में "धान खरीदी केन्द्र चलो अभियान चलाया।" कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, पदाधिकारी गण विभिन्न सोसायटियों में जाकर किसानों की समस्याओं की जानकारी लिया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बस्तर के छापधानपुर, तरन्वी, बरान्जी, टोकापाल धान खरीदी केन्द्र जा कर व्यवस्था का निरीक्षण किया तथा धान बेचने वाले किसानों से चर्चा किया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर जिले के खरीदें प्रशासक के धान खरीदी केंद्र में गए तथा वहां पर उपस्थित धान बेचने वाले किसानों एवं सोसायटी कर्मचारियों से चर्चा कर धान खरीदी में आ रही समस्याओं की जानकारी लिया।



संकरा धान खरीदी केंद्र में गए तथा वहां पर उपस्थित धान बेचने वाले किसानों एवं सोसायटी कर्मचारियों से चर्चा कर धान खरीदी में आ रही समस्याओं की जानकारी लिया। पूर्व उपमुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव महासमुंद के पिथौरा, राजाडोरा एवं बिलासगढ़ के सरसीवा सोसायटी गये। इन सोसायटियों में भी किसान बादराने, टोकन, कम तौल एवं उठाव के की समस्या से परेशान हो रहे हैं। दुर्ग शहर-ग्रामीण एवं भिलाई में ताम्रध्वज साहु, रविन्द्र चौबे, अरूण चोरा, कोण्डगांव में मोहन मरकाम, बलरामपुर में अमरजीत भात,



महासमुंद में द्वारिकाधीश यादव, चातुरी नंद, देवेन्द्र बहादुर सिंह, विनोद चंद्रकार, विनय जायसवाल, सकि जिले में रामकुमार यादव, बालेश्वर साहु, जगदलपुर एवं बस्तर ग्रामीण में लखेश्वर बघेल, धमवरी में अंबिका मरकाम, ओंकार साहु, गुरुमुख सिंह होरा, जांजगीर-चांपा में राघवेंद्र सिंह, ब्यास कश्यप, शेषराज हरबंस, राजनांदावां शहर एवं ग्रामीण में दलेश्वर साहु, भोलाराम साहु, हर्षिता बघेल, बालोदे में अनिला भंडिया, संगीता सिन्हा, कोरबा शहर एवं ग्रामीण में जयसिंह अग्रवाल, फूल सिंह राठिया, मोहित केरकेट्टा, पुरुषोत्तम कंवर, सूरजपुर में डॉ. प्रेमसाय सिंह टोकाम, खेलसाय सिंह, पारसनाथ राजवाडे, बिलासपुर शहर एवं ग्रामीण में अटल श्रीवास्तव, रश्मि सिंह ठाकुर, कांकर में कुंवर सिंह निषाद, विभिन्न सोसायटियों में जाकर किसानों की समस्याओं की जानकारी लिया गया। संतराम नेताम, शंकर ध्रुवा, रायगढ़ शहर एवं ग्रामीण में उमेश पटेल, विद्यावती सिदार, जशपुर में रामपुकार सिंह, लालजित सिंह राठिया, यु.डी. मिंज, विनय भागत, सुकामा में कवासी लखमा, राजमन

प्रमुख समाचार

भाजपा के 1 साल में छत्तीसगढ़ बढ़ाहाल हो गया - कांग्रेस

रायपुर। भाजपा सरकार अपने एक साल पूरे होने का जश्न मना रही है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सरकार के खिलाफ दिव्यांगजन आंदोलन करने को मजबूर हो गये है। दिव्यांग मुख्यांमत्री निवास घेरने को निकलने को विवश हो गये। यह सरकार के 1 साल की कथित सफलता का आईना है। भाजपा सरकार के 1 साल में छत्तीसगढ़ बढ़ाहाल हो गया है। जनकल्याणकारी योजनाएं बंद हो गयी है। सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन के कारण 1 साल में ही राज्य के खजाने पर 37000 करोड़ से अधिक का कर्जा हो गया है। युवाओं को मिलने वाला बेरोजगारी भता बंद हो गया। सरकारी नौकरी में भर्तियां बंद हो गयी। बिजली के दाम बढ़ गये। एक साल में ही साय सरकार जनता में अलोकप्रिय साबित हो गयी है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा की विष्णुदेव सरकार 1 साल में विफल साबित हो गई। राज्य में भ्रष्टाचार और कुशासन का दौर हावी है। साय सरकार के 1 साल में विष्णु का सुशासन तो दूर विष्णु की सरकार कहीं नहीं दिख रही। कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो गयी। एसपी कलेक्टर कार्यालय जला दिया गया। हत्याओं का नया रिकॉर्ड बन गया।

धान खरीदी केंद्र बिलाड़ी प्रभारी अनिमितता के चलते हटाए गए

रायपुर। रायपुर जिला में धान खरीदी केन्द्र बिलाड़ी में विजित के दौरान सहकारिता विभाग के जिला अधिकारी एनआर के चन्द्रवंशी द्वारा पाया गया कि धान उपार्जन केन्द्र बिलाड़ी के प्रभारी मुकेश वैष्णव द्वारा बिना डनेज के धान का स्टेकिंग कर दिया गया है। जबकि शासन की उपार्जन नीति में प्रावधान है कि धान का स्टेकिंग डनेज के ऊपर किया जाए। इस प्रकार श्री मुकेश वैष्णव द्वारा धान उपार्जन के नियमों का उल्लंघन करने के कारण उन्हें तत्काल प्रभाव से उपार्जन केन्द्र प्रभारी बिलाड़ी से हटा दिया गया है।

सिक्ख प्रीमियर लीग 6 दिसंबर से, कुल 12 टीमें लेंगी हिस्सा

रायपुर। शहीद भाई तार सिंह फाउंडेशन रायपुर द्वारा हर साल आयोजित किये जाने वाले नेशनल क्रिकेट प्रतियोगिता इस साल 6 दिसंबर से शुरु हो रही है। सिक्ख प्रीमियर लीग (एसपीएल) के आयोजन का यह सोलहवां वर्ष है। सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। संस्था के प्रमुख त्रिलोक सिंह काले ने बताया कि हर साल ये कोशिश होती है प्रायः सभी प्रमुख शहरों से आने वाली टीमें प्रतियोगिता में शामिल रहे। कुल 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं जिसमें प्रमुख रूप से जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, नांदेड, नागपुर, हैदराबाद, छत्तीसगढ़ की टीमें शामिल रहेंगी। बता दें यह क्रिकेट प्रतियोगिता वित्त 16 वर्षों से लगातार आयोजित की जा रही है। डब्ल्यूआरएस क्रिकेट ग्राउंड में ही मैच खेला जायेगा। फाइनल 16 दिसंबर को होगा। नियमावली हर साल होने वाले आयोजन की तरह ही है। जसमीत चावला,बलविंदर सिंह छबड़ा, बाबूलाल ज्वेलर्स का सहयोग हर साल मिलते रहा है। मुख्यत्त्व इस क्रिकेट प्रतियोगिता के आयोजन का उद्देश्य खेल के क्षेत्र में समाज की जो युवा प्रतिभाएं हैं उसे एक मंच प्रदान करना ताकि राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान आगे ले जा सकें।

राज्य प्रशासनिक सेवा के 14 अफसर आईएएस प्रमोट हुए

रायपुर। जनसंपर्क संचालक अजय अग्रवाल समेत राज्य प्रशासनिक सेवा के 14 अफसर आईएएस प्रमोट हो गए हैं। दिल्ली में आज हुई डीपीसी की बैठक में प्रमोशन पर मुहुर लग गई है। डीपीसी की बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन, एसीएस रेणु पिछे और सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव मुकेश बंसल शामिल थे। राज्य सरकार ने तीन दर्जन अफसरों का नाम डीपीसी के लिए भेजा था। तीन अफसर सौम्या चौरसिया, आरती वासनिक और तीर्थराज अग्रवाल का मामला लटक गया है। कोल चोटाला मामले में सौम्या चौरसिया जेल में बंद हैं। वहीं पीएससी चोटाला मामले में आरती वासनिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। उनके विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है। तीर्थराज अग्रवाल के खिलाफ चल रही जांच खत्म हो गई है। राज्य शासन ने उन्हें क्लीन चीट दे दी है। एक मामला कोर्ट में विचाराधीन है। पिछले प्रमोशन में चुके संतोष देवांगन और हीना नेताम को भी प्रमोट किया गया है। राज्य प्रशासनिक सेवा से आईएएस बने वाले अफसरों में संतोष देवांगन, हीना नेताम, अश्वनी देवांगन, रेणुका श्रीवास्तव, आशुतोष पांडेय, अजय अग्रवाल, रीता श्रीवास्तव, लोकेश चंद्रकार, प्रकाश सर्वे, गजेंद्र ठाकुर, लीना कोसम, तुनजा सलाम, वीरेंद्र बहादुर पंच भाई और सोमिल चौबे के नाम शामिल हैं।

असामाजिक तत्वों से बारोंडा गांव की महिलाएं परेशान

रायपुर। सफायर ग्रीन्स सोसाइटी के समीप स्थित बारोंडा गांव की लगभग 100 महिला श्रमिकों ने 3 दिसंबर को अपनी सुरक्षा को लेकर विधान सभा थाने में शिकायत दर्ज कराई। ये महिलाएं सफायर ग्रीन्स फेज 1, फेज 2 और विला में घरेलू कामकाज के लिए प्रतिदिन जाती हैं। महिला श्रमिकों का आरोप है कि सफायर ग्रीन्स और बारोंडा गांव के बीच रास्ते में कुछ असामाजिक तत्व शराब के नशे में उनसे दुर्व्यवहार करते हैं। वे अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं और कई बार महिलाओं के साथ हाथपाई करने की कोशिश करते हैं। महिलाओं ने बताया कि इस मामले में कई बार पुलिस को सूचित किया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। आज सामूहिक रूप से शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस ने उन्हें कक्षावाड़ का भरोसा दिया है। थाने में शिकायत के साथ सभी महिलाओं के हस्ताक्षर और बयान दर्ज किए गए हैं। इस गंभीर स्थिति पर सफायर ग्रीन्स सोसाइटी के निवासियों ने भी चिंता जताई है।

पूर्वोत्तर राज्यों से पढ़ने आई छात्राओं ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से की मुलाकात, सांस्कृतिक प्रस्तुति भी दी

शबरी कल्याण आश्रम की छात्राओं ने राज्यपाल डेका को दी असम-नागालैंड राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं

रायपुर। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका से शबरी कल्याण आश्रम की छात्राओं ने भेंटकर उन्हें असम और नागालैण्ड राज्यों के स्थापना दिवस पर बधाई और शुभकामनाएं दीं। केन्द्र सरकार के एक भारत-श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ के राजभवन में असम और नागालैंड राज्यों के स्थापना दिवस के अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ स्थापना दिवस मनाया गया। राज्यपाल श्री रमेन डेका ने इस अवसर पर कहा कि हमारा देश विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं का संगम है। विविधता में एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए

सभी राज्य एक दूसरे के स्थापना दिवस मनाते हैं। इसी कड़ी में अवसर पर इन राज्यों के लोगों को बधाई दी। रायपुर में बनवासी नागालैंड, त्रिपुरा की लगभग 40 बालिकायें अपनी पढ़ाई कर रही हैं। राज्यपाल श्री डेका को स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। राज्यपाल ने सभी बालिकाओं का छत्तीसगढ़ का राजकीय गमछा पहनाकर स्वागत किया। राज्यपाल श्री डेका ने अपने उद्घोषण में असम और नागालैंड राज्य की विशेषताओं को रेखांकित किया। राज्यपाल ने कहा कि असम और छत्तीसगढ़ की संस्कृति, अर्थव्यवस्था मिलती-जुलती है।

के साथ राजभवन पहुंचकर राज्यपाल श्री डेका से भेंट की। इस अवसर पर इन बालिकाओं ने पूर्वोत्तर राज्यों की लोक कला और लोक नृत्यों का प्रस्तुती भी दी। शबरी कल्याण आश्रम की ओर से इन बालिकाओं ने राज्यपाल श्री डेका को स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। राज्यपाल ने सभी बालिकाओं का छत्तीसगढ़ का राजकीय गमछा पहनाकर स्वागत किया। राज्यपाल श्री डेका ने अपने उद्घोषण में असम और नागालैंड राज्य की विशेषताओं को रेखांकित किया। राज्यपाल ने कहा कि असम और छत्तीसगढ़ की संस्कृति, अर्थव्यवस्था मिलती-जुलती है।

राजभवन के दरबार हॉल में असम एवं नागालैंड राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया। राज्यपाल ने स्थापना दिवस के

किया। उन्होंने कहा कि निर्वाचन नामावली को सभी जिला निर्वाचन अधिकारी व्यक्तिगत रूप से स्वयं देखे, उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होना चाहिए। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह ने चुनावी प्रक्रिया के दौरान होने वाली चुनौतियों और संभावित समस्याओं पर भी चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों को चुनाव के दौरान शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने, मतदाता जागरूकता बढ़ाने, और मतदान प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा की समय-समय पर निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किये गए दिशानिर्देशों के पालन प्रतिवेदन की समीक्षा की जा रही है।